



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)  
की अनुदानों की पूरक मांगों तथा वर्ष 2023-2024 का बजट

**निर्मला सीतारामन**  
वित्त मंत्री  
का  
भाषण

**Supplementary Demands for Grants of the Union Territory of Jammu & Kashmir  
(With Legislature) for 2022-2023 and Budget for 2023-2024**

**SPEECH  
OF  
NIRMALA SITHARAMAN**  
MINISTER OF FINANCE

**मार्च / March 13, 2023**



वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र  
(विधान मंडल सहित) की अनुदान की पूरक मांग और  
वर्ष 2023-24 के लिए बजट

निर्मला सीतारामन  
(वित्त मंत्री)  
का भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र ने अगस्त, 2019 में ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने इन परिवर्तनों का न केवल स्वागत किया है, बल्कि खुले दिल से इन परिवर्तनों को अपनाया भी है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। विद्युत, पर्यटन, सड़क संपर्क, शहरी क्षेत्र, स्वास्थ्य, खेल, जल और ग्रामीण विकास आदि जैसी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की गति उल्लेखनीय है।
2. जम्मू-कश्मीर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है जिसका उद्देश्य भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशामुक्त और पंच प्रण अर्थात् विकसित भारत के लक्ष्य, औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशान मिटा देना, नागरिकों के बीच अपनी मूल, एकता और कर्तव्य की भावना पर गर्व से प्रेरित होकर जम्मू-कश्मीर को रोजगार संपन्न बनाना है।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), अमृत सरोवर, स्वामित्व योजना, आजादी का अमृत महोत्सव, नशा मुक्त अभियान और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर देश में शीर्ष निष्पादन करने वालों में से एक रहा है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर कृषि आय, जीवन यापन में सुगमता, व्यापारिक सुगमता, पारदर्शिता, संधारणीय विकास लक्ष्यों की रैंकिंग और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शीर्ष निष्पादन करने वालों में शामिल है।

4. जम्मू और कश्मीर नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, संस्थानिक जन्म और पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत जैसी विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों के मामले में देश में अग्रणी है।
  5. जम्मू और कश्मीर ने सौभाग्य, उज्ज्वला, उजाला, वृद्धावस्था/विधवा और दिव्यांगजन पेंशन योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं, पोषण ट्रेकर, पोषण वाटिका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल, खेल के मैदान और युवा क्लब, पीएम किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं में 100 प्रतिशत संतुष्टि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत, 99.94 प्रतिशत आबादी को पाइप से पानी उपलब्ध कराया गया है और 57.84 प्रतिशत वैयक्तिक परिवार में नल कनेक्शन हैं। एलपीजी-डीबीटी (पहल) के अंतर्गत 31.77 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है। दुग्ध उत्पादन अब तक के सर्वाधिक 2594 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।
  6. "मेरे युवा मेरी शान, हर दिन खेल हर एक के लिए खेल" पहल के अंतर्गत लगभग 50 लाख युवाओं ने विभिन्न खेल कार्यक्रमों में भाग लिया है। शतरंज, रोइंग, टेबल टेनिस, पेनकाक्सिलैट, वुशु, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के राष्ट्रीय कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर में आयोजित किए गए, जहां देश भर के एथलीटों ने भाग लिया। खेलो इंडिया के अंतर्गत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी गुलमर्ग में की गई है जिसमें देश भर के एथलीटों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।
7. परिवर्तनकारी शासन:
- (क) जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुनियादी स्तर के लोकतंत्र की स्थापना, ज्ञान समाज का निर्माण और डिजिटल और भौतिक संपर्क के विस्तार जैसे कई सुधारों को शुरू करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं।
  - (ख) जम्मू-कश्मीर में अब 445 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन मोड में प्रदान की जा रही हैं। ऑफलाइन सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस प्रकार जम्मू और कश्मीर में नए डिजिटल युग की शुरुआत हुई है। ई-उन्नत पोर्टल विकसित किया गया है जो नागरिकों के लिए सभी सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एकल मंच पोर्टल है। सेवा वितरण की गुणवत्ता पर रियल टाइम फीडबैक को सक्षम करने वाली रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएसएस) विकसित की गई है और इस प्रणाली के माध्यम से 225 ई-सेवाओं को एकीकृत किया गया है। यह प्रणाली लोगों से सीधे फीडबैक लेता है

और लगभग 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सेवाओं को अच्छा और 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संतोषजनक बताया है। पारदर्शिता और जवाबदेही लाते हुए सभी ऑनलाइन सेवाओं को अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम से जोड़ा जा रहा है जो कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय उपायों में से एक है। जम्मू और कश्मीर सरकार "जीवन-यापन में सुगमता" के लिए डिजिटल जम्मू और कश्मीर के विचार को बढ़ावा दे रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता जम्मू-कश्मीर में शासन की पहचान बन गए हैं।

- (ग) विकास कार्यों के निष्पादन में असाधारण स्तर की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व इस तथ्य से प्रवर्धित होता है कि बिना ई-निविदा, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जा रहा है। ऑन-साइट सुविधा के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड (प्रूफ) मोबाइल एप्लिकेशन और कार्यों के 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन के माध्यम से अपलोड किए गए जियो-टैग फोटोग्राफ के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाता है। नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी विकास कार्यों को सशक्तिकरण/जनभागीदारी पोर्टल पर रियल टाइम के आधार पर सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। पोर्टल पर 78,811 से अधिक कार्य जनता के लिए दर्शाए जा रहे हैं। इन्हें कोई भी कहीं से भी कभी भी मोबाइल पर देख सकता है।
- (घ) नागरिकों के आसान पहुंच के लिए जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों के जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसावी के स्कैन किए गए डेटा के रूप में भूमि अभिलेखों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण किया गया है और "आपकी ज़मीन आपकी निगरानी" पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। भूमि अभिलेखों के 8 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को स्कैन किया गया है और "आप की जमीन आप की निगरानी" पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। भूमि धारकों को त्रिभाषी भूमि पासबुक उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में जारी की जा रही है। लगभग 30 लाख पासबुक जारी की गई हैं और 67 लाख लोगों ने साइट को देखा है। भूमि उपयोग परिवर्तन को एक बड़े उपाय के रूप में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। जम्मू और कश्मीर स्वामित्व योजना के अंतर्गत "आबादी देह" क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला संघ राज्य क्षेत्र बन गया है।
- (ङ) जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र जिला स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण का आकलन करने के लिए जिला सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है। अब तक दो रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं।

- (च) वर्ष 2022-23 के दौरान दो नई अनूठी पहल अर्थात 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समग्र विकास के लिए चयनित 285 पंचायतों (प्रति ब्लॉक एक पंचायत) में "आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम" और चयनित आकांक्षी नगर के समग्र विकास के लिए "आकांक्षी नगर विकास कार्यक्रम" शुरू किया गया है। इस प्रगति को मापने के लिए एक पंचायत विकास सूचकांक और नगर विकास सूचकांक भी विकसित किया गया है।
- (छ) "आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम" के भाग के रूप में, "बैंक टू विलेज" (बी2वी4) कार्यक्रम का चौथा चरण दिनांक 15 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2022 तक संघ राज्य क्षेत्र में आयोजित किया गया था। 'बैंक टू विलेज' कार्यक्रम के चौथे चरण के दौरान 4290 अधिकारियों ने पंचायती राज संस्थाओं में गतिशीलता लाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित वितरण तंत्र में दक्षता पैदा करने के मुख्य उद्देश्यों से प्रभारी अधिकारियों के रूप में नामित पंचायतों का दौरा किया था। बी2वी4 कार्यक्रम में 8.20 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। बी2वी4 के जन अभियान के दौरान 5914 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अब तक कुल 12,84,058 केसीसी जारी किए गए हैं। पंचायतों में स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत 37,930 व्यक्तियों को शामिल किया गया, ई-पीडीएस पोर्टल पर राशन कार्ड धारकों का 100 प्रतिशत डेटा राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है, 49,526 नए परिवारों को शामिल करते हुए 95,959 गोल्डन कार्ड जारी किए गए थे। पंचायतों में 3,573 जल गुणवत्ता क्षेत्र परीक्षण किट वितरित किए गए, खनन विभाग द्वारा 75,759 ई-चालान जारी किए गए हैं, 8.89 लाख व्यक्तियों ने 'आपकी जमीन आपकी निगरानी' पोर्टल को देखा है और 7.04 लाख भूमि पासबुक राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए थे।
- (ज) "आकांक्षी नगर विकास" कार्यक्रम के भाग के रूप में, 'माई टाउन माई प्राइड 2.0' कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान 100 अधिकारियों ने शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर समितियों) का दौरा किया था। इसका मुख्य ध्यान नगरपालिका वित्त और शहर विशिष्ट योजनाओं की तैयारी पर था ताकि हमारे नगरों और शहरों को आकांक्षी शहर बनने राह को सक्षम बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में 4.49 लाख लोगों ने भाग लिया था। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के अंतर्गत 1,33,524 परिवारों को घर-घर तक जागरूकता अभियान हेतु कवर किया गया था, 2,740 स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस जारी किए गए थे और शहरी स्थानीय निकायों में 5,002 व्यक्तियों को स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत कवर किया गया था। 38,973 गोल्डन

कार्ड जारी किये गए थे, 508 शहर योजना तैयार किये गये थे, 53,923 भूमि पासबुक जारी किये गये थे और 2,649 इनहेरिटेंस म्यूटेशन किया गया था।

- (झ) आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 34 माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने वर्ष 2022 में जम्मू और कश्मीर के 17 जिलों में जनता से बातचीत करने और सरकार की नीतियों पर बुनियादी स्तर की प्रतिक्रिया का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया था। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, व्यापार, उद्योग आदि के अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया; जिससे जम्मू और कश्मीर में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और पहलों प्रबंधन और कार्यान्वयन में सुधार की उम्मीद है।
- (ञ) पिछड़े ब्लॉकों के उत्थान के लिए "आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम" भी शुरू किया गया है और 1 करोड़ रुपये प्रति ब्लॉक सहित 44 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं।
- (ट) जम्मू और कश्मीर 300+ कार्यालयों में अधिकतम 97 प्रतिशत निपटान दर सहित ई-ऑफिस को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला संघ राज्य क्षेत्र है। दरबार मूव की प्रथा समाप्त हो गई है।
- (ठ) कोषागारों और बैंकों का दौरा किए बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से करों और उपयोगकर्ता शुल्कों के भुगतान की सुविधा के लिए ई-ग्रास शुरू किया गया है। राजस्व संग्रहण विभाग के पोर्टल ई-ग्रास प्रणाली से एकीकरण की प्रक्रिया में है।
- (ड) जम्मू और कश्मीर विभागों के वैधानिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु ऑनलाइन ई-लेखापरीक्षा अनुप्रयोग शुरू करने वाला पहला संघ राज्य क्षेत्र है। ई-लेखापरीक्षा पोर्टल रियल टाइम के आधार पर बीईएएमएस/जेकेपीएवाईएसवाईएस के माध्यम से विभागों की वित्तीय जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए एक एकीकृत एकल मंच उपकरण है।
- (ढ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने एकीकृत डैशबोर्ड के रूप में ई-एचआरएमएस प्रारंभ किया है जिसमें नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, मासिक वेतन पर्ची, आयकर कटौती और भविष्य निधि जैसी महत्वपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पोर्टल पर 3.65 लाख से अधिक कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया है, जिससे कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को बनाए रखने के पारदर्शिता में सुधार हुआ है। कर्मचारियों के लिए संपत्ति रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लगभग 3.50 लाख कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति रिटर्न दाखिल किया है।
- (ण) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य प्रमुख लाभार्थी योजनाओं को विशेष उप राज्यपाल अभियान के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों के लिए संतुष्ट किया जाएगा। जन

अभियान के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों के नामांकन हेतु विभिन्न स्थानों पर उप राज्यपाल विशेष अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसका समाधान करने के लिए सभी प्रवासी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर उपयुक्त रूप से तैनात किया गया है।

#### 8. विकास में तेजी लाना:

- (क) वर्ष 2018-19 में विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के अंतर्गत 9229 कार्य/परियोजनाएं पूरी की गई थी, वर्ष 2019-20 में 12637 कार्य/परियोजनाएं पूरी की गई थी। वर्ष 2020-21 में 21943 कार्य/परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के अंतर्गत 50,627 कार्य/परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इससे पता चलता है कि विकास की गति कई गुना बढ़ गई है और वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 70,000 कार्य/परियोजनाएं पूरी होने की संभावना है।
- (ख) प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन की गति तेज कर दी गई है। व्यय 39133 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 29 परियोजनाएं पूर्ण/पर्याप्त रूप से पूरी हो चुकी हैं और अन्य 03 परियोजनाएं वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना है।
- (ग) जम्मू-कश्मीर सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क संपर्क अत्यंत आवश्यक है। मैं गरिमामयी सभा को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2018 तक, जम्मू-कश्मीर में हर साल औसतन 1500 से 1600 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाता था। वहीं निर्माण अब दोगुना से अधिक बढ़कर 3200 किलोमीटर हो गया है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रतिदिन 12 किमी से अधिक लंबी सड़क का मैकडैमाइजिंग कर रहा है। जम्मू-कश्मीर हर गांव तक सड़क की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है।
- (घ) 3117 करोड़ रुपये की लागत से 8.45 किलोमीटर काजीगुंड-बनिहाल सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे अब श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय 10 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है।
- (ङ) कश्मीर के 2023 के अंत तक देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने की संभावना है।
- (च) बड़े राजमार्गों और सुरंग परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से सड़क अवसंरचना प्रगति पर है। वर्तमान में अनेक राजमार्ग परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम अगले 2-3 वर्षों में पूरा हो रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को काफी राहत मिली है।



- (छ) श्रीनगर-सोनमर्ग रोड पर 6.5 किमी लंबी जेड-मोड़ सुरंग पर काम तेज गति से चल रही है और यह चालू वित्त वर्ष के दौरान 2378 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो जाएगी, जो पर्यटकों को सर्दियों में भी खूबसूरत जगह घूमने का अवसर प्रदान करेगा।
- (ज) जम्मू और कश्मीर में आने वाले छह लेन वाले दिल्ली-अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 135 किलोमीटर खंड का निर्माण शुरू हो गया है। इससे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का समय घटकर 6 घंटे रह जाएगा।
- (झ) 14.20 किमी समानांतर निकास सुरंग के साथ दो-लेन की 14.15 किमी की द्वि-दिशात्मक (बी-डायरेक्शन) जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- (ञ) एनएच 144ए के अखनूर-पुंछ खंड पर 4 सुरंगों (4.85 किलोमीटर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- (ट) अखनूर-पुंछ सड़क (एनएच-144ए) पर 35.38 किलोमीटर की दोहरी लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- (ठ) जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों के विस्तार का कार्य प्रगति पर है।
- (ड) विजयपुर, जम्मू में एम्स और अवंतीपोरा कश्मीर में एम्स का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
- (ढ) 07 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और 15 नर्सिंग कॉलेज चालू किए जाएंगे।
- (ण) दो राज्य कैंसर संस्थानों को पूरी तरह कार्यशील बनाया जाएगा। इस वर्ष पूर्ण होने वाले 140 स्वास्थ्य संस्थानों के पुनर्निर्माण/उन्नयन पर 881 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।
- (त) एमबीबीएस की प्रवेश क्षमता 500 से बढ़कर 1100 सीटों और पीजी सीटों की संख्या 513 से बढ़कर 593 हो गई है।
- (थ) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) के साथ अभिसरण में जम्मू और कश्मीर "सेहत" स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, लाभार्थियों का पंजीकरण 83.97 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
- (द) बिजली उत्पादन क्षमता को 3 साल में दोगुना किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों में ही 3000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं को पुनर्जीवित कर पटरी पर लाया गया है। 1000 मेगावाट पकल दुल और 624 मेगावाट किरू पर काम जोरों पर है। 850 मेगावाट रैटले को प्रदान किया गया है। एनएचपीसी द्वारा 1856 मेगावाट की सावाकोट परियोजना के लिए निर्माण पूर्व गतिविधियां शुरू की गई हैं।

- (ध) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू अपने स्वयं के परिसर से कार्य कर रहा है और भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू इस वर्ष अपने परिसर में स्थानांतरित हो जाएगा।
- (न) विश्व बैंक से 250 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता वाली 213 परियोजनाओं को झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट ऑर्गनाइजेशन द्वारा लिया गया था। 159 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 54 परियोजनाएं निष्पादन के उन्नत चरण में हैं।
- (प) "हर गाँव एक अमृत सरोवर" की पहल के तहत 4041 अमृत सरोवरों की पहचान की गई है, जिनमें से 2420 पूरे हो चुके हैं और शेष 15 अगस्त 2023 से पहले पूरे हो जाएंगे।
- (फ) जी20 शिखर बैठक की तैयारी में, जम्मू और कश्मीर सरकार सड़क, शहरी और पर्यटन क्षेत्रों के तहत प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करेगी।
- (ब) मुख्य सचिवों के दो राष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्य योजना के सभी घटकों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

#### 9. औद्योगिक विकास:-

- (क) जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 का फोकस नए निवेश को आकर्षित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का पोषण करना है। पहले कदम के रूप में, जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति 2020 अधिसूचित की गई है।
- (ख) कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना 7 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ लागू की जा रही है।
- (ग) शिल्प उद्योग को नई गति प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष घोषित कारखंडर योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- (घ) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और 47,092 कनाल के लैंड बैंक सहित 64,058 करोड़ रुपये की लगातार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जिसमें 2,93,689 युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने की क्षमता है।
- (ङ) 2022-23 के दौरान, जनवरी, 2023 तक कुल 1,547.87 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। चालू वित्त वर्ष के अंतिम 10 महीनों के दौरान पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में अब तक का सबसे अधिक निवेश हुआ है।

- (च) पिछले तीन वर्षों में, 500 स्टार्ट अप सामने आए हैं जिन्होंने एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की है।
- (छ) सरकार जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और वैश्विक मांग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जीआई टैग जैसे प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी इनपुट और इस तरह के अन्य ढांचागत समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

#### 10. रोजगार:-

- (क) जम्मू और कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया गया है। शत-प्रतिशत भर्ती मैरिट पर आधारित है। भर्ती के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया अपनाई जाती है। वेतन स्तर-5 तक के साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।
- (ख) 33,426 पदों को भर्ती एजेंसियों को भेजा गया है, जिसमें से जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के 2,436 चयनों सहित 25,450 चयन किए गए हैं। शेष फास्ट-ट्रैक भर्ती के लिए प्रक्रियाधीन हैं।
- (ग) मिशन युवा, ग्रामीण आजीविका मिशन, हिमायत, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जम्मू-कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेएंडकेआरईजीपी), जम्मू-कश्मीर शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेएंडकेयूईजीपी), महिला उद्यमिता कार्यक्रम, अवसर आदि के तहत मुमकिन और तेजस्वनी जैसी कई स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। 2022-23 में 2,02,749 युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत कवर किया गया है तथा मार्च, 2023 के अंत तक इसमें 2,37,000 युवाओं को कवर करने का लक्ष्य है।
- (घ) तदनुसार, जम्मू और कश्मीर में उच्च श्रम शक्ति भागीदारी है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मजदूरी रोजगार लगभग संतुल्य हो गया है।

#### 11. अर्थव्यवस्था की स्थिति:-

बाधाओं के बावजूद जम्मू और कश्मीर ने विकास की गति को बनाए रखा है और राजस्व और विकास दोनों पक्षों के तहत व्यय को तेजी से प्रबंधित किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समग्र जीएसडीपी वृद्धि 14.64 प्रतिशत (पहली संशोधित) रही है। सेक्टरल ब्रेकअप अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिखाता है।

प्राथमिक क्षेत्र:	6.58 प्रतिशत
माध्यमिक क्षेत्र:	8.59 प्रतिशत
तृतीयक क्षेत्र:	18.69 प्रतिशत

अर्थव्यवस्था सही गति पर है और सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अर्थव्यवस्था के 10 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है और जीएसटी, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी के तहत संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। फरवरी, 2023 तक जीएसटी संग्रह 6666.04 करोड़ रुपये है; जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 14.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एमएसटी संग्रह फरवरी, 2023 को समाप्त होने तक 1444.45 करोड़ रुपये है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 401.44 करोड़ रुपये की तुलना में फरवरी, 2023 तक स्टाम्प संग्रह 438.88 करोड़ रुपये है, जो 9.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में 1443.07 करोड़ की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी, 2023 को समाप्त होने तक उत्पाद शुल्क संग्रह 14.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए 1658.35 करोड़ रुपये रहा है; समग्र कर संग्रह ने महत्वपूर्ण वृद्धि और लचीलापन दिखाया है।

12. इस सीजन में हमने पर्यटकों का अच्छा प्रवाह देखा है और पिछले वर्ष दिसंबर, 2022 तक 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। इसमें से 26.73 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया, जो वर्ष 2016 में पिछले उच्चतम 12.99 लाख से दोगुने से अधिक है। विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग गोंडोला को पहली बार लगभग 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
13. सूखे और ताजे फलों का निर्यात बढ़ रहा है और फरवरी, 2023 के अंत तक लगभग 18.15 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया जा चुका है।

#### 14. वित्तीय समावेशन:-

- (क) आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जीईसीएल (1.0, 2.0 और 3.0) के तहत 2488.04 करोड़ रुपये के 65,907 उधारकर्ता लाभान्वित हुए हैं और 16,49,706 परिवारों को मुफ्त चावल और 16,97,820 परिवारों को दालें प्रदान की गईं। पीएम-स्वनिधि योजना के तहत 20,596 लाभार्थियों को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के साथ स्ट्रीट वेन्डर्स के लिए विशेष ऋण सुविधा वितरित की गई है। 7,86,077 केसीसी (फसल) खाताधारकों को 5794.12 करोड़ रुपये और 1,54,604 केसीसी-पशुपालन और मत्स्य पालन (एच एंड एफ) खाताधारकों को 825.86 करोड़ रुपये का क्रेडिट प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 2,42,828 लाभार्थियों को 5251.22 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

(ख) बैंकों से लगभग 1018 करोड़ रुपये के ऋण के साथ 50,000 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो "बैंक टू विलेज प्रोग्राम" के चौथे चरण और "माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम" के दूसरे चरण के दौरान पहचाने गए लगभग 75,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करती हैं।

#### 15. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

(क) सभी व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और हम 100 प्रतिशत आधार सीडिंग के साथ इन योजनाओं के संबंध में 100 प्रतिशत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2022-23 के दौरान अब तक डीबीटी के माध्यम से 39 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 1378 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

(ख) पिछले एक साल में, जम्मू और कश्मीर ने प्रति दिन 11 लाख ई-लेनदेन दर्ज किए, जो लगभग 48,000 ई-लेनदेन प्रति घंटे है।

#### 16. बजट 2023-24:

16.1 वर्ष 2023-24 के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के बजट की प्राथमिकताएं अंतर्निहित विषयों पर आधारित होंगी:

- i. सुशासन
- ii. बुनियादी लोकतंत्र का सुदृढीकरण
- iii. सतत कृषि का संवर्धन
- iv. निवेश और औद्योगिक विकास का सुगमिकरण
- v. रोजगार सृजन।
- vi. त्वरित विकास और समावेशी वृद्धि।
- vii. महिला सशक्तिकरण।
- viii. सामाजिक समावेशन।
- ix. पांच साल के भीतर जीडीपी दोगुनी करना।

16.2 जम्मू-कश्मीर के लिए बजट 2023-24 फिर से 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करेगा, जो जम्मू और कश्मीर को विकास का मॉडल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक संकेतक है। वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,500 करोड़ रुपये है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 41,491 करोड़ रुपये है।

- 16.3 बजट के पूंजी घटक में काफी वृद्धि हुई है। अपेक्षित राजस्व प्राप्तियां 1,06,061 करोड़ रुपये हैं जबकि राजस्व व्यय 77,009 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए 29,052 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष उपलब्ध होगा।
- 16.4 पूंजीगत प्राप्तियां 12,439 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 41,491 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। निर्धारित बजट का 35 प्रतिशत विकास और अवसंरचना परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

## 17. सामाजिक-आर्थिक विकास:

### 17.1 कृषि, बागवानी और रेशम उत्पादन क्षेत्र:

- (क) जम्मू और कश्मीर समग्र कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी जो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कृषि क्षेत्र में क्षैतिज परिवर्तन करेगी। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों की अवधि में 5,012 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह जम्मू और कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास के एक नए पथ पर लाएगा, क्षेत्रों के उत्पादन को दोगुना करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा और क्षेत्रों को सतत और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा। यह जम्मू और कश्मीर में कृषि समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के एक नए चरण की शुरुआत करेगा और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2,87,910 लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अगले पांच वर्षों की अवधि में 18,861 नए व्यावसायिक उद्यम बनाए जाएंगे।
- (ख) इस समग्र कृषि विकास योजना के तहत, पूर्ण मूल्य श्रृंखला (फुल वेल्यू चेन) और एकत्रीकरण नेटवर्क के साथ 67,000 मीट्रिक टन नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण स्थान बनाया जाएगा। अगले पांच वर्षों की अवधि में शहद उत्पादन तीन गुना और कोकून उत्पादन को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1350 मीट्रिक टन किया जाएगा।
- (ग) गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में उगाए जाने वाले खाद्यान्नों और उच्च मूल्य वाली फसलों का बाजार-आधारित उत्पादन किया जाएगा।
- (घ) कृषि शक्ति को बढ़ाकर 2.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर किया जाएगा ताकि मानव कठिनाइयों को कम किया जा सके, खेती की लागत में कमी लाई जा सके और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
- (ङ) बासमती, राजमाश, काला जीरा, मुश्कीबुदजी, केसर और शहद जैसे विशेष उत्पादों के निर्यात से होने वाली कमाई भी बढ़ेगी।

- (च) सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।
- (छ) फसल गहनता (दोगुनी/तिगुनी फसल) के माध्यम से सकल फसली क्षेत्र वर्तमान 11.34 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.50 लाख हेक्टेयर हो जाएगा।
- (ज) विभिन्न योजनाओं के तहत परिकल्पित फसलोपरांत प्रबंधन पहलों के माध्यम से उत्पादन और कटाई के बाद के नुकसान को 20-25 प्रतिशत से घटाकर 15-18 प्रतिशत किया जाएगा।
- (झ) रेशम कीट पालन के लिए किसानों को राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ) से खरीदे गए उन्नत नस्लों के रेशम-कीट बीज प्रदान करना। विभाग द्वारा किसानों को बीज की आपूर्ति अत्यधिक रियायती दरों पर की जाती है।
- (ञ) कोकून की पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तर्ज पर कोकून के पालन में सहायता के लिए 200 किसानों को पालन उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- (ट) चावकी पालने वालों को पाले गए चावकी कीटों के वितरण के लिए रेशम कीट बीज के उष्मायन के लिए चावकी और पालन केंद्र का निर्माण।
- (ठ) फल पौधों में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए फेरोमोन चारा जाल (बेयटिड ट्रैप्स) का उत्पादन।
- (ड) कृषि में स्वचालन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रोबोटिक्स।
- (ढ) भदरवाह, जिला डोडा में गुच्छी, राजमाश और अन्य स्थानीय वनों/कृषि उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों के लिए पैकेजिंग इकाइयां।
- (ण) भदरवाह, जिला डोडा में देवदार की लकड़ी के तेल निष्कर्षण और पैकेजिंग इकाई की स्थापना।
- (त) बहुपक्षीय एजेंसी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत वित्त पोषण के साथ वर्ष 2023-24 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- (थ) उच्च घनत्व वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और बागों के कायाकल्प के लिए डिजाइनर पौधों का उत्पादन।
- (द) बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए उत्पादकों को मंच प्रदान करके जम्मू और कश्मीर में कृषि विपणन को मजबूत करना, बागवानी उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए सीधे संपर्क के लिए क्रेता-विक्रेता लिंकेज और किसानों/उत्पादकों को अधिक लाभ सुनिश्चित करना।

- (ध) चेरी, स्ट्रॉबेरी, आलूबुखारा, नाशपाती, आड़ू, लीची और विदेशी/जैविक सब्जियों की तरह खराब होने वाले फलों के हवाई परिवहन के लिए पर्वाज योजना के तहत सब्सिडी सहायता।
- (न) नरवाल जम्मू में 2000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर और सोपोर के माजबुग में 2500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा।
- (प) संघ राज्य क्षेत्रों के फलों को प्रमाणित करने और बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उपज की जीआई टैगिंग।
- (फ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण पौधशाला विकास योजना के तहत क्षेत्र बढ़ाने के लिए सहायता, हेक्टेयर में आम और खट्टे फलों का वृक्षारोपण, हेक्टेयर में कीवी फल वृक्षारोपण, हेक्टेयर में सेब, अखरोट और स्टोन के फलों का वृक्षारोपण।

**कृषि और बागवानी क्षेत्रों के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 2526.74 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 1239.45 करोड़ रुपये अधिक है।**

### **17.2 पशु, भेड़ पालन और मत्स्य पालन क्षेत्र:**

- (क) समग्र कृषि विकास योजना के तहत दूध उत्पादन में 75 प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रसंस्करण श्रृंखला में प्रवेश करने वाले दूध को अगले पांच वर्षों की अवधि में तीन गुना कर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर माँस और ऊन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।
- (ख) अगले पांच वर्षों में ट्राउट और कार्प उत्पादन को दोगुना किया जाना है।
- (ग) दुग्ध उत्पादन में 25 से 45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ-साथ दुग्ध संग्रह/चिलिंग में 2.0 से 8.5 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) की वृद्धि हुई। अगले पाँच वर्षों में लगभग 3.6 हजार मीट्रिक टन मूल्य वर्धित उत्पाद बाजार में प्रवेश करेंगे।
- (घ) अधिक आजीविका सुरक्षा के लिए भेड़ पालकों/प्रजनकों की आय में वृद्धि। ऊन प्रसंस्करण उद्योगों को रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा।
- (ङ.) पशुधन की बढ़ती आबादी और उद्योग का समर्थन करने के लिए चारा विकास में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में, संघ राज्य क्षेत्रों में चारे की कमी को 80 प्रतिशत तक कम करने के लिए।

**पशु, भेड़ पालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 629.70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 267.84 करोड़ रुपये अधिक है।**



### 17.3 स्वास्थ्य और कल्याण:

- i. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग नियमित रूप से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और जनता की स्वास्थ्य देखभाल और रोगी अनुभव में सुधार के लिए विस्तारित आउटरीच के माध्यम से भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) मानदंडों को पूरा कर रहा है। हितधारकों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं की रैंकिंग नियमित रूप से की जाती है।
- ii. कठुआ में आधुनिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन।
- iii. कैंसर संस्थान, जम्मू का संचालन।
- iv. सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कैथलैब की स्थापना और संचालन।
- v. अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और कुपवाड़ा जिलों के लिए क्षय रोग (टीबी) मुक्त स्थिति प्राप्त करना।
- vi. सभी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों के परिचालन में संतुष्टि।
- vii. कर्मयोगी अभियान के तहत समुदाय के बीच योग की विस्तारित पहुंच के लिए 1000 आयुष चिकित्सा सहायकों (पैरामेडिक्स) के लिए योग और कल्याण का प्रशिक्षण।
- viii. सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर/जम्मू में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत।
- ix. सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू और सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में बेहतर रोगी देखभाल के लिए नियंत्रण और कमान केंद्र की स्थापना।
- x. विशेष रूप से डोडा/किश्तवाड़/रामबन जैसे क्षेत्रों में आपातकालीन निदान के लिए अवसंरचना, जनशक्ति और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से दुर्घटना संभावित जिलों में अभिघात परिचर्या (ट्रॉमा सेंटर) सुविधाओं का सुदृढीकरण।
- xi. 25 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, 57 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, 04 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और एक 50 बेड वाले गंभीर देखभाल (क्रिटिकल केयर) ब्लॉक की स्थापना।
- xii. कायाकल्प के अंतर्गत कवर की जाने वाली सभी सुविधाएं।
- xiii. गहन देखभाल इकाइयों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार।

- xiv. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण तंत्र और रोगी रिकॉर्ड (एबीएचए) में सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के तहत मॉड्यूल का विस्तार।
- xv. जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और मोबाइल चिकित्सा इकाइयां।
- xvi. सभी जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी के लिए प्रभावी प्रबंधन।
- xvii. नशा मुक्त अभियान के तहत ओपीडी/आईपीडी सुविधाओं का उन्नयन/अपडेशन।
- xviii. सी-सेक्शन डिलीवरी में कम से कम 20% की कमी।
- xix. स्कूली बच्चों और आबादी के अन्य वर्गों की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग।
- xx. टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्य भर में नेटवर्किंग का कार्यान्वयन (टेली-मानस)।
- xxi. ई-संजीवनी का कार्यान्वयन
- xxii. दवा वितरण प्रणाली की स्थापना - पायलट आधार पर आवश्यक आपूर्ति / दवा के लिए ड्रोन की शुरुआत और ड्रोन स्टेशनों का निर्माण।
- xxiii. टेली बाहरी-रोगी विभाग (टेली-ओपीडी) का कार्यान्वयन।
- xxiv. स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत डिजी सर्विलांस प्रणाली।
- xxv. पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जांच।
- xxvi. गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) और अन्य रोगों की 100 प्रतिशत जांच/निगरानी।
- xxvii. उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की प्रारंभिक पहचान और प्रसवोत्तर देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना।
- xxviii. पूर्ण (100 प्रतिशत) टीकाकरण कवरेज।
- xxix. एनीमिया मुक्त जम्मू और कश्मीर को सुदृढ़ करना।
- xxx. रेडियोथेरेपी उपकरण सभी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- xxx. सभी 7 मेडिकल कॉलेजों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज संबंधी रोग (सीओपीडी) एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्ट (एसटीईएमआई) स्ट्रोक और कीमोथेरेपी के उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 2097.53 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 214.97 करोड़ रुपये अधिक है।

## 17.4 ग्रामीण विकास:

- (क) गांवों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के सभी घटकों के कार्यान्वयन के साथ सभी गांवों को खुले में शौच से फ्री प्लस स्टेट्स (ओडीएफ प्लस) घोषित किया जाएगा।
- (ख) कौशल विकास, मिशन युवा उद्योग और वाणिज्य, स्कूली शिक्षा, कृषि आदि जैसे विभागों में कौशल संबंधी अवसंरचना के प्रशिक्षण और अभिसरण के लिए रोजगार उन्मुख व्यवसायों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ हिमायत 2.0 का शुभारंभ।
- (ग) एनआरएलएम-यूएमईडी के तहत, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेआरएलएम) जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम का गठन करके लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उनके निवारण और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए शिकायतें दर्ज की जा सकें। जम्मू और कश्मीर में 10,000 अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया जाएगा, जिसकी कुल संख्या 1,00,000 हो जाएगी।
- (घ) "हर पंचायत-पंचायत घर" की पहल के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत 1500 नए पंचायत घरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत घरों को 100 प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- (ङ) आरजीएसए के अंतर्गत पीआरआई सदस्यों के 3 लाख से अधिक कार्य दिवसों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही अन्य प्रगतिशील राज्यों के एक्सपोजर दौरों के लिए बजट में वृद्धि की जाएगी।
- (च) आवासहीन परिवारों के लिए जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत 40,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।
- (छ) 87,250 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण और 2500 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण।
- (ज) 2080 से अधिक गांवों में मल-अपशिष्ट के प्रबंधन के प्रावधान के साथ ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रावधान होगा।
- (झ) 2080 से अधिक गांव स्वच्छ और गंदगी मुक्त हो जाएंगे और ये गांव अपशिष्ट जल के प्रावधानों के साथ प्लास्टिक मुक्त होंगे।

- (ज) पीआरआई आवास कम लागत वाली टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाया जाएगा।
- (ट) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, इस योजना के अंतर्गत 400 लाख कार्य दिवस सृजित किए जाएंगे और यह 100 प्रतिशत ऑनलाइन जॉब कार्ड जारी करने के साथ इसे पूरी तरह से भरा जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए, लगभग वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 4169.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

### 17.5 विद्युत क्षेत्र:

- (क) शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली आपूर्ति के दैनिक घंटों में सुधार।
- (ख) ट्रांसफार्मर क्षति दर में कमी, पारेषण और वितरण/सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी।
- (ग) अप्रैल 2023 तक 60 प्रतिशत ऊर्जा की खपत स्मार्ट मीटर के माध्यम से करने और 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं को वर्ष 2024-25 तक स्मार्ट मीटर की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है।
- (घ) मौजूदा 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशनों पर नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य और महत्वपूर्ण टावरों पर संरक्षण/प्रतिस्थापन कार्य और नए टावरों को लगाना।
- (ङ) इस सीमावर्ती क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए गुरेज की ग्रिड कनेक्टिविटी।
- (च) सर्दियों के दौरान सोनमर्ग को 24x7 बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जेड-मोहर सुरंग के माध्यम से भूमिगत केबलिंग।
- (छ) श्री अमर नाथ जी की पवित्र गुफा को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए नुनवान में भूमिगत केबलिंग।
- (ज) 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू किया जाएगा।
- (झ) नए 220 केवी और 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता 575 एमवीए और 100 एमवीए तथा मौजूदा 220 केवी और 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता को 725 एमवीए और 754 एमवीए तक बढ़ाना।

- (ज) महत्वपूर्ण लाइनों पर एचटीएलएस कंडक्टर और सामान्य एसीएसआर कंडक्टरों के माध्यम से 220 केवी और 132 केवी स्तर पर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना। इससे वर्तमान वहन क्षमता लगभग दो गुना बढ़ जाएगी, जिससे मौजूदा ग्रिड स्टेशनों का बेहतर उपयोग होगा। इसके अलावा, इससे विश्वसनीय और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- (ट) एलटी/एचटी नेटवर्क की लंबाई में 1324.073 किलोमीटर की वृद्धि।

विद्युत क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 1964.90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

### 17.6 पर्यटन और संस्कृति:

- (क) "पर्यटन मिशन" की पहल के रूप में 75 नए गंतव्य, 75 स्फू/धार्मिक स्थल, 75 नए सांस्कृतिक/विरासत स्थल और 75 नए ट्रेक विकसित किए जा रहे हैं और खोले जा रहे हैं ताकि पर्यटन उद्योग का आर्थिक लाभ दूर-दराज और अब तक अनछुए क्षेत्रों तक पहुंच सके। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देना वर्ष 2023-24 के लिए "पर्यटन मिशन" का महत्वपूर्ण घटक होगा।
- (ख) कारवां पर्यटन, एक नया पर्यटन स्थल खोला जाएगा जो पर्यटकों को एक नई गतिविधि प्रदान करेगा और न्यूनतम अवसंरचना परियोजनाओं के साथ अनदेखे क्षेत्रों और ऑफ-बीट गंतव्यों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। सोनमर्ग में इको मोबिलिटी सुविधा बनाई जाएगी, ताकि पर्यटक पर्यावरण को प्रभावित किए बिना थाजीवास ग्लेशियर की यात्रा कर सकें।
- (ग) पर्यटन क्षेत्र में नए स्थल को जोड़ने के लिए, विस्टा डोम सेवाओं को रेलवे के सहयोग से बारामूला-बनिहाल खंड पर परिचालित किया जाएगा।
- (घ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो/कार्यक्रम/उत्सव आयोजित किए जाएंगे।
- (ङ) जम्मू और श्रीनगर के दोनों शहरों में वाटर पार्को का विकास।
- (च) वुलर और मानसबल झीलों में जल खेल गतिविधियों को शुरू करने के लिए वुलर झील में नाव क्लब सह जल खेल केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। डल झील, मानसर झील और भागलियार बांध स्थल पर जल आधारित गतिविधियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी।

- (छ) अठवाजन पार्क, श्रीनगर और खदिनयार पार्क, बारामूला को मनोरंजक गतिविधियों, साहसिक क्षेत्रों और बच्चों के खेलने के क्षेत्रों के लिए विकसित किया जाएगा।
- (ज) गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग, दूधपथरी यूसमार्ग, भद्रवाह और पटनीटॉप जैसे नए स्थलों पर खेल-कूद गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- (झ) श्री अमर नाथ जी यात्रा के दौरान तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बालटाल, चंदेनवारी एवं नवनिर्मित सुरंग काजीगुंड तथा टीटवाल और गुरेज में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सूचना केंद्रों को स्थापित किया जाएगा।
- (ञ) संघ राज्य क्षेत्र में पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहारों को बढ़ावा देना।
- (ट) पर्यटन स्थलों पर महिला गाइडों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (ठ) बांदीपुरा, शोपियां, अनंतनाग, किशतवाड़, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और पुंछ में संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- (ड) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों को ई-पुस्तकालयों में बदला जाएगा।
- (ढ) शेरगरी परिसर में दो पुराने विरासत स्थल और पुराने श्री प्रताप सिंह (एसपीएस) संग्रहालय श्रीनगर को विरासत स्थलों के संरक्षण कार्यक्रम के तहत जीर्णोद्धार और संरक्षित किया जाएगा।
- (ण) जम्मू में अभिनव थियेटर और श्रीनगर में टैगोर हॉल की मरम्मत, जीर्णोद्धार और उन्नयन किया जाएगा।
- (त) प्रतिभा की खोज गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
- (थ) श्रीनगर के पुराने सचिवालय के पत्थर भवन में नया "कला संग्रहालय" बनाया जाएगा।
- (द) सांबा में ऐतिहासिक किला, त्राल में नरस्तान स्मारक, पुलवामा, श्रीनगर में हारीपर्वत किला और रियासी में जनरल जोरावर सिंह पैलेस को पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

पर्यटन और संस्कृति क्षेत्रों के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 457.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 54.31 करोड़ रुपये अधिक है।

## 17.7 जल शक्ति विभाग:

### I. पीएचई सेक्टर:

- (क) जम्मू-कश्मीर के सभी 18.36 लाख घरों में वर्ष 2023-24 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन होंगे। प्रत्येक परिवार को नियमित, दीर्घकालिक और स्थायी आधार पर न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) और निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस 10500 की पुष्टि) के साथ पेयजल प्रदान किया जाएगा।
- (ख) वर्ष 2023-24 के दौरान 60 जल आपूर्ति योजनाओं के पूरा होने की संभावना है।
- (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) आधारित टैंकर सेवा शुरू की जाएगी।
- (घ) परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) 20 प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता।
- (ङ) पूरे जम्मू और कश्मीर में उपभोक्ता रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।

### II. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र:

- (क) तवी बैराज का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा किया जाएगा।
- (ख) सिंचाई नहरों से समय पर गाद निकालना।
- (ग) इष्टतम जल गहराई बनाए रखने के लिए होकरसर वेटलैण्ड स्लुइस गेट्स का पूरा होना।
- (घ) झेलम बाढ़ प्रबंधन की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए इसके भाग-ख का कार्यान्वयन।

जल शक्ति विभाग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 7161 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 3191 करोड़ रुपये अधिक है।

## 17.8 आवासन और शहरी विकास क्षेत्र:

- (क) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 घरों को जल नल कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

- (ख) डल झील, अनंतनाग की प्रदूषित नदी खंड और शेष शहरों के सीवेज प्रबंधन को सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।
- (ग) देविका परियोजना के तहत 13.60 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता जोड़ी जाएगी।
- (घ) चरणबद्ध तरीके से 89.83 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए जाएंगे, जिससे 6,20,565 लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।
- (ङ) अमृत-2.0 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सभी चिन्हित जल निकायों का चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है, इसके अलावा श्रीनगर में झेलम रिवर फ्रंट और जम्मू में तवी रिवर फ्रंट जैसे नदी तटों को स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से विकसित किया जा रहा है और इसे वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा किया जाएगा।
- (च) संघ राज्य क्षेत्र के सभी 78 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हासिल कर लिया गया है और 16 यूएलबी ओडीएफ + हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी शहरी स्थानीय निकायों में 100 प्रतिशत ओडीएफ + हासिल किया जाएगा।
- (छ) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान 18,934 आवासइकाइयों को पूरा किया जाना है।
- (ज) शहरी गरीब प्रवासियों के लिए किराये के आवास तक पहुंच में सुधार के लिए, सुंजवाँ, जम्मू में 336 फ्लैटों को अपग्रेड किया जा रहा है और वर्ष 2023-24 के दौरान शहरी गरीबों/ प्रवासियों को प्रदान किया जाएगा।
- (झ) गुंड-ए-रक्षा और छतरहामा, श्रीनगर और जम्मू के कोट भलवाल में बड़े पैमाने पर आवासान/नए टाउनशिप/किफायती आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के लिए विकसित किए जाएंगे।
- (ञ) वर्ष 2023-24 के दौरान "स्मार्ट सिटी मिशन" के तहत 130 परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है। इसमें बेहतर अवसंरचना, स्मार्ट शासन के लिए प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, स्मार्ट गतिशीलता, स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र, हरित स्थानों का विकास, स्ट्रीट लाइटनिंग और विरासत को बढ़ावा देना होगा।



- (ट) जम्मू और श्रीनगर दोनों राजधानी शहरों में एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों राजधानी शहरों में यात्रियों को मदद मिलेगी और शहरों में यातायात भीड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- (ठ) वर्ष 2023-24 के दौरान रेल, सड़क और वायु जैसे विभिन्न परिवहन साधनों को एकीकृत करने के लिए टर्मिनल अवसंरचना के रूप में कटरा में एक इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) बनाया जाएगा।
- (ड) चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- (ढ) इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- (ण) शहर की गतिशीलता योजनाओं के लिए नीति को शुरू करना।
- (त) श्रीनगर, जम्मू और अन्य प्रमुख शहरों में "लेडीज हाट" और लेडीज विशेष बाजारों (एक्सक्लूसिव मार्केट) की स्थापना करना।
- (थ) एकता मॉल का निर्माण।

आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 2928.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 674.78 करोड़ रुपये अधिक है।

## 17.9 शिक्षा क्षेत्र:

### I स्कूल शिक्षा:

- (क) सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए "आओ स्कूल चलें" के तहत गहन नामांकन अभियान जारी रखा जाएगा।
- (ख) वर्ष 2023-24 के दौरान गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 2000 किंडरगार्टन स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- (ग) वर्ष 2023-24 के दौरान 10 आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिनमें आदिवासी छात्रों और कमजोर वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता के आधार पर इन आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।

- (घ) छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक कक्षा में एलसीडी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 1000 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी।
- (ङ) 100 उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को खिलाड़ियों के लिए चेंज रूम सहित खेल अवसंरचना प्रदान की जाएगी।
- (च) उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 500 अतिरिक्त क्लास रूम प्रदान किए जाएंगे, जिससे 20,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
- (छ) प्राथमिक कक्षाओं के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी।
- (ज) कमजोर वर्गों के सभी प्राथमिक छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी।
- (झ) सभी स्कूलों में पेयजल सुविधा और लिंग आधारित शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ञ) 500 स्कूलों को आईसीटी प्रयोगशालाएं और 100 व्यावसायिक प्रयोगशालाएं स्कूलों में स्थापित की जाएंगी।
- (ट) अवसंरचना/गुणवत्ता शिक्षा के तहत बारामूला, शोपियां, किश्तवाड़ और राजौरी जिले में एक-एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा ताकि प्रवासी लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके।
- (ठ) छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर (प्रत्येक जोन में एक प्रयोगशाला) में 188 वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित किए जाएंगे।
- (ड) स्कूलों में डिजिटल समानता, साक्षरता और आर्थिक विकास के अलावा नई शिक्षण पद्धतियों में सुधार करने में मदद करने के लिए 40 रोबोटिक प्रयोगशालाएं (प्रत्येक जिले में दो प्रयोगशालाएं) स्थापित की जाएंगी।
- (ढ) सभी छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए योग प्रशिक्षण को सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

## II उच्च शिक्षा:

- (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को अपनाने में जम्मू और कश्मीर सबसे आगे है और वर्ष 2023-24 में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
- (ख) वर्ष 2023-24 में, 32 कॉलेजों की एनएएसी मान्यता पूरी हो जाएगी।
- (ग) वर्ष 2023-24 में समर्थ "ईआरपी ईगॉव सुइट", पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कॉलेजों के एचआरएम, एस्टेट और इन्वेंट्री का प्रबंधन करना और छात्र जीवन चक्र के साथ केंद्रीकृत दाखिले को शुरू करना है।
- (घ) वर्ष 2023-24 के दौरान उच्च शिक्षा परिषद को कार्यशील बनाया जाएगा।
- (ङ) वर्ष 2023-24 में 08 कॉलेज भवन और 04 छात्रावास भवन के तैयार होने की संभावना है।
- (च) वर्ष 2023-24 में 04 ऑडिटोरियम और 04 बहुउद्देशीय हॉल तैयार होने की संभावना है।
- (छ) वर्ष 2023-24 में 02 पुस्तकालय ब्लॉक तैयार होने की संभावना है।

स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 1521.87 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 193.61 करोड़ रुपये अधिक है।

### 17.10 सड़क संपर्क (सड़क और पुल):

- (क) कुल मिलाकर वर्ष 2023-24 के दौरान सभी योजनाओं के तहत सड़कों की ब्लैक-टॉपिंग का 6000 किलोमीटर का लक्ष्य हासिल किए जाने की उम्मीद है।
- (ख) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)-XXVIII के साथ नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण के तहत 1292 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 253 नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्राथमिकता दी गई है और जिसे 2023-24 के दौरान निष्पादित किया जाएगा।
- (ग) वर्ष 2022-23 के दौरान 20 वर्ष पूरे करने वाले पुलों की सुरक्षा लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 10 वर्ष पूरे करने वाले पुलों के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

- (घ) सड़क/पुल आस्तियों के रख-रखाव और सड़क सुरक्षा उपायों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- (ङ) वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत 60 चालू पुलों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- (च) वर्ष 2023-24 के दौरान सभी प्रमुख सड़कों पर "पासिंग बे" का निर्माण किया जाएगा।
- (छ) वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमजीएसवाई-III कार्य शुरू किए जाएंगे।

सड़क और पुल क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 4062.87 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 98.99 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 17.11 उद्योग और वाणिज्य:-

- (क) वर्ष 2023-24 के दौरान नए औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिए 29 प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- (ख) निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना के सृजन के लिए जम्मू और श्रीनगर में औषधीय संस्थाओं की स्थापना हेतु निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेमपोरा, श्रीनगर और मीरान साहिब, जम्मू में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की जा रही है।
- (ग) "एक जिला एक उत्पाद" का मुख्य उद्देश्य निर्यात के लिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। इस संबंध में जिला श्रीनगर और जम्मू को स्थानीय उत्पादों के निर्यात के लिए पूरे भारत के 75 जिलों में से चुना गया है।
- (घ) जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेएंडकेआरईजीपी) के तहत वर्ष 2023-24 में 1500 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 9000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ 30 करोड़ की मार्जिन मनी शामिल है।
- (ङ) औद्योगिक क्षमता के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।
- (च) क्षमता निर्माण/स्टार्ट-अप संवर्धन पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- (छ) रोजगार में वृद्धि के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए टर्नओवर प्रोत्साहन प्रदान करना।
- (ज) हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत ब्रांडिंग के साथ गुणवत्ता प्रमाणन की शुरुआत।

- (झ) स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिया बनाना।
- (ञ) "जीवन यापन सुगमता" और "व्यापारिक सुगमता" पर अनुपालन को कम करना।
- (ट) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास नीति अधिसूचित की जाएगी।
- (ठ) समाधान 2.0 को लागू किया जाएगा।
- (ड) एमएसएमई का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ गठजोड़ किया जाएगा।
- (ढ) निजी निवेश को समर्थन देने के लिए नीतिगत ढांचा पेश किया जाएगा।
- (ण) एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
- (त) निर्यात केंद्रों का निर्माण।
- (थ) विनिर्माण क्षेत्र सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल को अपनाना।

उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 741.79 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 283.40 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 18. सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र:

- (क) चरणबद्ध तरीके से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- (ख) 124300 को छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों से संबंधित प्री-मैट्रिक छात्रों (1-8 वीं) को शामिल किया जाएगा।
- (ग) सभी शिशु देखभाल संस्थानों को आधुनिक पैटर्न पर विकसित किया जाएगा जिसमें कैदियों के लिए सर्वोत्तम जीवन स्थितियां होंगी। 19 बाल आश्रमों और 12 नारी निकेतनों में 1700 निवासियों को शामिल किया जाएगा।
- (घ) सभी 20 जिलों में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किए जाएंगे।
- (ङ) महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) महिला शक्ति केंद्र का निर्माण

- (च) जीपीएस सक्षम महिला हेल्पलाइन की स्थापना।
- (छ) कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण।
- (ज) विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 98.92 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

#### 19. जनजाति कल्याण:

- (क) 24 अनुसूचित जनजाति और गुज्जर/बक्करवाल छात्रावासों को तैयार किया जाएगा।
- (ख) खानाबदोश आबादी के लिए 07 पारगमन आवासों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (ग) आदिवासी आबादी के लिए दूध गांव और स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- (घ) दूध, मटन, भेड़ ऊन, चमड़ा आदि जैसे जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार संपर्क का सृजन।
- (ङ) आदिवासी परिवारों को उनके माल और मवेशियों के मौसमी प्रवास के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (च) खानाबदोश आबादी की शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक स्थिति पर नज़र रखना।

जनजातीय मामलों के लिए, वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 446.76 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 13.97 करोड़ रुपये अधिक है।

#### 20. कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास:

- (क) प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत श्रीनगर के ज़ेवन में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के रूप में 936 फ्लैटों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 1984 पारगमन आवास तैयार हो जाएंगे।
- (ख) कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम-पैकेज के तहत 6000 पदों में से 355 पदों को वर्ष 2023-24 के दौरान भरा जाएगा।

- (ग) एसआरई के तहत कश्मीरी/जम्मू प्रवासियों के लिए नकद सहायता और खाद्यान्न जारी रहेगा।

उपरोक्त पैकेज के लिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के तहत वर्ष 2023-24 में लगभग 1102 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 267 करोड़ रुपये अधिक है।

## 21. युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता:

- (क) स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं को बैंकों और मिशन यूथ के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेएंडकेआरईजीपी) और जम्मू और कश्मीर शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेएंडकेयूईजीपी) के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ग) स्वरोजगार योजनाओं यथा प्रारंभिक पूंजीगत निधि (सीड कैपिटल फंड), युवा स्टार्टअप ऋण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम एवं महिला रोजगार कार्यक्रम के तहत 8100 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए 3200 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (घ) जम्मू और श्रीनगर, प्रत्येक में 02 विशाल रोजगार मेलों सहित 40 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
- (ङ) वर्ष 2023-24 के दौरान जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां, बांदीपुर और कुपवाड़ा में 06 मॉडल जीविका केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- (च) अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता ट्रेकिंग प्रणाली की स्थापना।
- (छ) विदेशों में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
- (ज) युवाओं के कौशल विकास के लिए युवा मंडलों को जीवंत बनाया जाएगा।

## 22. खेल संबंधी पहलें:

- (क) वर्ष 2023-24 के दौरान खेल कार्यकलापों में 70 लाख युवाओं को शामिल करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के हर नुक्कड़ और कोने में अधिक से अधिक खेल कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे।

- (ख) फेंसिंग, वुशू और जिम्नास्टिक में उच्च निष्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- (ग) दो योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे, एक मौलाना आजाद स्टेडियम, जम्मू में और एक बखशी स्टेडियम, श्रीनगर में।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्र में जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए खेलों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
- (ङ) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" अभियान के तहत विभिन्न खेल आयोजनों में 25 राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी।
- (च) खेल सीखने की प्रक्रिया के संस्थानीकरण के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वुशू अकादमियों की स्थापना की जाएगी।
- (छ) खेलों और पैरा-एथलेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

### 23. कौशल विकास:

- (क) अन्य विभागों के साथ अभिसरण में अनुकूलित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षणों के माध्यम से 60,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का कौशल विकास।
- (ख) 8 आकांक्षी/सीमावर्ती जिलों अर्थात जम्मू, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, बारामूला, बांडीपुर और कुपवाड़ा में स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलिहुड प्रमोशन (संकल्प) के तहत कौशल परिदृश्य में सुधार किया जाएगा।
- (ग) सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन/निष्पादन लेखा परीक्षा की जाएगी।
- (घ) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
- (ङ) यूनिसेफ के माध्यम से वंचित युवाओं के लिए विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुशिल्पों (पॉलिटेक्निक), महाविद्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं का समावेशी कौशल मानचित्रण आयोजित किया जाएगा।
- (च) प्रशिक्षुओं को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण कौशल प्रदान करके महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हंदवाड़ा, पत्तन और तंगधार में कार्यशाला ब्लॉकों का निर्माण।



- (छ) "कौशल केन्द्रों" का निर्माण।
- (ज) चलित प्रशिक्षण कार्यशाला (ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन व्हील्स) शुरू की जाएगी।
- (झ) गतिशील जिला और संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कौशल विकास योजना तैयार की जाएगी जिसमें सभी कौशल शामिल किए जाएंगे।
- (ञ) इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक से कौशल ऋण।

युवा सशक्तिकरण, रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और खेल कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 396.63 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

#### 24. वानिकी और पर्यावरण:

- (क) हरित जम्मू-कश्मीर अभियान को वनीकरण पर एक अम्ब्रेला कार्यक्रम के रूप में चलाया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान 1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
- (ख) "हर गांव हरियाली" वृक्षारोपण अभियान के तहत 4290 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
- (ग) "वन बीट गार्ड, वन विलेज प्रोग्राम" के तहत गांव की आम भूमि, कछारी और बंजर भूमि में पौधे लगाने के लिए फाइबर, भोजन, चारा और लकड़ी (टिंबर) की प्रजातियों की अन्य रोपण सामग्री प्रदान की जाएगी।
- (घ) वन/संरक्षित क्षेत्रों में स्वच्छ आर्द्रभूमि का संरक्षण एवं संवर्धन।
- (ङ) वन क्षेत्रों में चारा उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
- (च) वन क्षेत्रों के सभी तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा।
- (छ) "प्लास्टिक मुक्त वन" पहल, एक अभियान के रूप में शुरू की जाएगी।
- (ज) स्कूलों में 6000 पर्यावरण क्लब पंजीकृत किए जाएंगे।
- (झ) वुलर झील से गाद निकालने का काम मिशन मोड में किया जाएगा।
- (ञ) जंबू चिड़ियाघर तैयार हो जाएगा और वर्ष 2023-24 में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

- (ट) प्रो-एक्टिव एंड रिस्पांसिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेन्टल सिंगल-विंडो हब (परिवेश) 2.0 लागू किया जाएगा।

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 207.75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 68.52 करोड़ रुपये अधिक है।

**25. खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले:**

- (क) पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को राशन का 100 प्रतिशत वितरण।
- (ख) स्टोर इन्वेंट्री का डिजिटलीकरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का पूर्ण कार्यान्वयन।
- (ग) उधमपुर, किशतवाड़, रामबन और डोडा में कम्प्यूटरीकृत वेईंग पुल बनाए जाएंगे।
- (घ) बांदीपुर, शोपियां, पुलवामा, डोडा और बडगाम में कार्य मानक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
- (ड) नगरोटा, राजौरी, खानबल, कुलगाम और बीरवाह में भंडारण गोदामों की पुनःउत्थान और सौंदर्यकरण।
- (च) सार्वजनिक वितरण सेवाओं के वितरण में ई-रुपया लेनदेन का कार्यान्वयन।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 390.87 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 21.49 करोड़ रुपये अधिक है।

**26. विज्ञान और प्रौद्योगिकी:**

- (क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) घटक "ख" के तहत, 2023-24 के दौरान लगभग 4000 सौर कृषि पंप स्थापित किए जाएंगे।
- (ख) पीएम-कुसुम घटक "ग" के तहत, मौजूदा कृषि ग्रिड से जुड़े पंपों के स्थान पर वर्ष 2023-24 के दौरान 5000 सौर कृषि पंप स्थापित किए जाएंगे।

- (ग) जम्मू सौर शहर परियोजना के तहत, 200 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के कुल स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 2023-24 में लगभग 80 मेगावाट हासिल किए जाने हैं, जिसमें लगभग 20,000 घर शामिल हैं।
- (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा वित्त पोषित घरेलू क्षेत्र के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के तहत, वर्ष 2023-24 के दौरान 10 मेगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए 3000 परिवारों को कवर किया जाएगा।
- (ङ) श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, श्रीनगर शहर में लगभग 3 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- (च) पहले चरण में श्रीनगर शहर के 50 भवनों और विभिन्न जिलों में 20 अन्य सरकारी भवनों की पहचान ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदान करने के लिए की जाएगी। सभी सरकारी भवनों को मिशन मोड में कवर करने का लक्ष्य होगा।
- (छ) वर्ष 2023-24 के दौरान आईपीपी को 2 से 10 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की लगभग 72 मेगावाट की कुल क्षमता आवंटित की जाएगी।
- (ज) चन्नी हिम्मत, जम्मू में ऊर्जा भवन का निर्माण 2023-24 के अंत तक पूरा किया जाएगा।
- (झ) उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, लाल मंडी, श्रीनगर के परिसर के भीतर नवाचार और प्रसार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना स्टार्ट-अप के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- (ञ) संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुगंधित और औषधीय पौधों के प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे।
- (ट) वर्ष 2023-24 के दौरान 100 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ठ) उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जम्मू की स्थापना की प्रक्रिया राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से शुरू की जाएगी।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 109.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 37.00 करोड़ रुपये अधिक है।**

## 27. सहकारिता विभाग:

- (क) सहकारी बैंकों को लाभप्रद बनाने में सक्षम बनाने के लिए उनका पुनर्गठन।
- (ख) सभी सहकारी बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान अपनाया जाएगा और उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू की जाएगी।
- (ग) डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली (डीबीएमएस) में सभी सहकारी समितियों के आंकड़ों का डिजिटलीकरण और संकलन।
- (घ) 80 नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी और उन्हें कार्यशील बनाया जाएगा। इससे सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा।
- (ङ) सभी कारीगर सहकारी समितियों के सदस्यों को कारीगर क्रेडिट कार्ड से संतुष्ट किया जाएगा।
- (च) जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और बडगाम में सुपर बाजारों का आधुनिकीकरण शुरू किया जाएगा और अन्य स्थानों पर नए सहकारी सुपर बाजारों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।
- (छ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण, जिससे उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रूप से जोड़ने (लिंगिंग) हेतु सक्षम बनाया जा सके।
- (ज) महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना।

सहकारी समितियों के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 25.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 10.00 करोड़ रुपये अधिक है।

## 28. राजस्व विभाग

- (क) पिछले 20 वर्षों के पैतृक संपत्ति (लैंगेसी) डेटा को स्कैन, डिजिटलाइज़ किया जाएगा और राष्ट्रीय सामान्य (जेनेरिक) दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पोर्टल / संघ राज्य क्षेत्र डेटा केन्द्र पर अपलोड किया जाएगा।

(ख) उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के लिए पंजीकरण दस्तावेजों के रिकॉर्ड को किसी भी नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा उपकरणों की स्थापना।

राजस्व विभाग के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 59.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 12.65 करोड़ रुपये अधिक है

## 29. परिवहन विभाग:

- (क) परिवहन क्षेत्र में पुराने वाहनों की स्क्रेपिंग नीति
- (ख) महिलाओं के लिए बसों और गुलाबी टैक्सियों की शुरुआत।
- (ग) केवल महिला बस ड्राइवर और कंडक्टरों को शामिल करना।

परिवहन विभाग के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 54.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 9.39 करोड़ रुपये अधिक है

## 30. सुरक्षा संबंधी कार्यकलाप:

- (क) जम्मू-कश्मीर के सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस सीमा चौकियां बनाई जाएंगी।
- (ख) अपराध संगठन को मजबूत किया जाएगा।
- (ग) जेलों में प्रमुख टावरों/जैमरों का निर्माण और स्थापना।
- (घ) पुलिस शहीदों के आश्रितों के लिए 02 छात्रावासों का निर्माण।
- (ङ) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में पुलिस आवासीय कॉलोनियों का निर्माण।
- (च) पुलिस अस्पतालों और पुलिस पब्लिक विद्यालयों का उन्नयन।
- (छ) सशस्त्र बलों (भूतपूर्व सैनिकों) के आश्रितों के लिए 02 छात्रावासों का निर्माण।
- (ज) नवीनतम प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों की खरीद के साथ मौजूदा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
- (झ) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, श्रीनगर में नारकोटिक प्रयोगशाला और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू में विष विज्ञान और नारकोटिक प्रयोगशाला का निर्माण।

- (ज) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू और श्रीनगर में भौतिकी और बैलिस्टिक प्रभाग का निर्माण और उन्नयन।
- (ट) सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पूरी की जाएगी।
- (ठ) सार्वजनिक स्थानों पर कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) के साथ सीसीटीवी कैमरे।

सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों के लिए, वर्ष 2023-24 हेतु 1197 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

### 31. वित्तीय सुधार/ई-शासन पहल:

- (क) जम्मू-कश्मीर के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस का विस्तार किया जाएगा।
- (ख) ई-बिलिंग प्रणाली लोक निर्माण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (पीडब्ल्यूओएमएएस) का सभी इंजीनियरिंग विभागों में विस्तार किया जाएगा।
- (ग) सभी सेवाओं और लाभार्थी-उन्मुख योजना को 100 प्रतिशत ऑनलाइन किया जाएगा।
- (घ) पीएम-गति शक्ति को सभी विभागों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
- (ङ) विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी वाहनों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों में सार्वभौमिक संचरण और वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
- (च) जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम में बौद्धिक टिकट प्रबंधन प्रणाली (इंटेलिजेंट टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम) शुरू किया जाएगा।
- (छ) मोबाइल ऐप के विकास के माध्यम से ऑनलाइन जनगणना प्रबंधन प्रणाली का सृजन।
- (ज) जीएसटी डेटा ट्रांसगुलेशन का परिचय।
- (झ) जीएसटी की ई-इनवॉयस प्रणाली का सृजन।
- (ञ) जीएसटी-इन का जीएसटी-प्राइम में परिवर्तन।
- (ट) ई-वे बिल को फास्टैग और वाहन से जोड़ना।

(ठ) आईटी विभाग द्वारा एकल विशिष्ट हेल्पलाइन का सृजन।

(ड) अंतर-राज्य ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण ढांचा।

### 32. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूरक अनुदान:

(क) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल अनुदान 1,12,950 करोड़ रुपये था। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक वर्ष के दौरान सेवाओं और आवश्यक उद्देश्यों पर खर्चों को कम करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से संबंधित मांगों के तहत अनुदान से अधिक 3711.7176 करोड़ रुपये की राशि वापस ली जाएगी। डीए में 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, सहायता अनुदान, सब्सिडी और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों सहित अन्य राजस्व व्यय, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं, जनजातीय उप-योजनाओं, कौशल विकास परियोजनाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के तहत पूंजीगत आवंटन में वृद्धि से वेतन में वृद्धि के कारण यह व्यापक रूप से आवश्यक हो गया था।

(ख) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से 3711.7176 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए पूरक जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (01) प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

### 33. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान:

(क) वित्त वर्ष 2023-24 की कुल प्राप्तियां 1,18,500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें से 1,06,061 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां, 12,439 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां और 30,000 करोड़ रुपये अर्थोपाय अग्रिम हैं। कर और गैर-कर दोनों का राजस्व 34,942 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय सहायता के रूप में 35,581 करोड़ रुपये और सीएसएस/पीएमडीपी के रूप में 26786 करोड़ रुपये दिए जाने हैं।

(ख) इन प्राप्तियों को देखते हुए इसका कुल व्यय 1,18,500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें पूंजीगत व्यय 41,491 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 77,009 करोड़ रुपये होगा।

(ग) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (02) को 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से

1,48,500 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

**34. राजकोषीय संकेतक:**

(क) वर्ष 2023-24 के लिए कर/जीडीपी अनुपात 8.82 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के 7.77 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) वर्ष 2023-24 के लिए ऋण/जीडीपी अनुपात 49 प्रतिशत है।

(ग) वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2,30,727 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

35. अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पूरक बजट (01-04-2022 से 31-03-2023 के लिए) और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2023-24 के बजट को इस गरिमामय सभा के आगे विचार के लिए प्रस्तुत करती हूँ।



**Supplementary Demand for Grants of the Union Territory of  
Jammu and Kashmir (with Legislature) for 2022-23 and  
Budget for 2023-24**

**Speech of  
Nirmala Sitharaman**

*Minister of Finance*

**Mr. Speaker Sir,**

1. The Union Territory of Jammu and Kashmir has witnessed unprecedented level of development in various sectors since historic changes in August, 2019. The people of Jammu and Kashmir not only welcomed but have embraced these changes with open heart. The law and order situation has improved appreciably. Pace of development in all critical sectors such as power, tourism, road connectivity, urban sector, health, sports, water and rural development etc., is remarkable.
2. Jammu and Kashmir has entered the Amrit Kaal with the aim of a fear-free, corruption-free, drug-free and employment-rich Jammu and Kashmir inspired by Panch Pran i.e Goal of developed India, Remove any trace of colonial mindset, Take pride in our roots, Unity and Sense of duty among the citizens.
3. The Jammu and Kashmir has been among top performers in the country for implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Amrit Sarovar, SVAMITVA Scheme, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Nasha Mukh Abhiyan and Renewable Energy Development. Besides, Jammu and Kashmir is among top performers in Agriculture Income, Ease of Living, Ease of Doing Business, Transparency, Sustainable Development Goals and One Nation One Ration Card.

4. Jammu and Kashmir leads the nation under various health parameters like Neo-natal Mortality Rate, Infant Mortality Rate, Sex ratio at birth, Institutional births and percentage of fully immunized children.
5. Jammu and Kashmir has achieved 100% saturation in schemes like Saubhagya, Ujjwala, Ujala, Old Age/Widow and Disability Pension Scheme, SC/ST/Minority, Pre-Matric and Post-Matric Scholarship Schemes, Poshan Tracker, Poshan Vatikas, Prime Minister's Matru Vandana Yojana, Kisan Credit Card Scheme, Swachh Bharat Mission, Drinking Water, Play field & Youth Clubs, PM Kisan Samman Nidhi, Soil Health Card and Public Distribution System. Besides, under JJM, 99.94% population has been provided with piped water and 57.84% individual households have tap connections. Under LPG-DBT (PAHAL) 31.77 lakh beneficiaries have been covered. Milk production has reached highest ever 2594 Thousand Metric Tons.
6. Under the initiative "My Youth My Pride, Har Din Khel Har Ek Kay Liye Khel" nearly 50 lakh youth have participated in different sports activities. National events in the disciplines of chess, rowing, table tennis, pencaksilat, wushu, volleyball and badminton have been conducted in Jammu and Kashmir wherein athletes from all over the country participated. National winter games under Khelo India have been hosted at Gulmarg in which athletes from across the country participated with great fervour.
7. **Transforming Governance:**
  - a) Jammu & Kashmir Government has made concerted efforts to introduce multitude of reforms like establishment of grassroot level democracy, creation of knowledge society and expansion of digital and physical connectivity.
  - b) More than 445 services are now being provided in online mode in Jammu and Kashmir. Offline services have been completely stopped thus ushering a new digital era in Jammu and Kashmir. **e-UNNAT** Portal has been developed which is the single platform portal to make all government services available for the citizens. Rapid Assessment

System (RAS) enabling real time feedback on quality of service delivery has been developed and 225 e-Services have been integrated through this system. The system provides direct feedback from people and nearly 85 % respondents rated the services as good and 7% as satisfactory. One of the appreciable step taken by the Government of Jammu and Kashmir is that all the online services are now being linked with Public Service Guarantee Act, bringing in huge transparency and accountability. The Jammu and Kashmir Government is promoting the idea of digital Jammu and Kashmir for "Ease of Living". Transparency, accountability and timeliness have become hallmark of governance in Jammu & Kashmir.

- c) The exceptional level of transparency and accountability in execution of development works is amplified through facts such as no work is being allotted without e-tendering, Administrative Approval and Technical Sanction. No payment is made without geo-tagged photographs uploaded through Photographic Record of On-site Facility (PROOF) mobile application and 100% physical verification of works. To ensure citizen participation, all the developmental works are put in public domain on real-time basis on the EMPOWERMENT/JANBHAGIDARI portal. More than 78,811 works are being reflected on the portal for public viewing. Anyone can access these from anywhere anytime on a mobile.
- d) Land records have been completely digitized and made available on "Aapki Zameen Aapki Nigrani" portal in the shape of scanned data of Jamabandi, Girdawari, Mutation and Mussavi of all the 20 districts of Jammu and Kashmir for free access to the citizens. More than 8 crore documents of land records have been scanned & hosted on "Aap ki Zameen Aap Ki Nigrani" portal. Trilingual Land passbooks in Urdu, Hindi and English are being issued to landholders. Around 30 Lakh pass books have been issued and 67 lakh persons have visited the site. As a major step, change of land use has been brought under the

purview of Public Service Guarantee Act. Jammu and Kashmir has become first Union Territory to distribute property cards in "Abadi Deh" areas under SVAMITVA scheme.

- e) The Union Territory of Jammu and Kashmir is the first among States/Union Territories to have District Good Governance Index for assessing the public service delivery at district level. Two reports have been brought out so far.
- f) Two new unique initiatives "Aspirational Panchayat Development Programme" with an objective to provide financial assistance of Rs. 10.00 Lakh to selected 285 Panchayats (one Panchayat per Block) for their holistic development and "Aspirational Towns Development Programme" for holistic development of selected Aspirational Towns has been launched during 2022-23. A Panchayat Development Index and Town Development Index have also been developed to measure the progress.
- g) As a part of "Aspirational Panchayat Development Programme", the fourth phase of "Back to Village" (B2V4) programme was conducted across the Union territory from 15<sup>th</sup> of October to 3<sup>rd</sup> of November, 2022. During the fourth phase of 'Back to Village' programme, 4290 officers visited the designated Panchayats as Prabhari Officers with the core objectives of energizing Panchayati Raj Institutions and inculcating the efficiency in delivery mechanism related to various government schemes. More than 8.20 lakh people participated in B2V4 programme. 5914 Kisan Credit Cards were issued during Jan Abhiyan of B2V4, with total of 12,84,058 KCCs issued so far. 37,930 persons were covered under self-employment drive in the Panchayats, 100% data of Ration Card Holders on e-PDS portal have been shifted to Ration Card Management System portal; 95,959 golden cards were issued covering 49526 new families; 3,573 water quality field testing kits were distributed in the Panchayats; 75,759 e-challan have been

issued by Mining Department, 8.89 lakh persons accessed 'Apki Zamin Apki Nigrani' Portal and 7.04 lakh land passbooks were issued by the Revenue Department.

- h) As a part of "Aspirational Town Development" Programme, 100 officers visited the Urban Local Bodies (Municipal Corporations/ Municipal Councils/Municipal Committees) during the 2<sup>nd</sup> phase of 'My Town My Pride 2.0' Programme. The major focus was on the municipal finances and preparation of city specific plans to enable our towns and cities embark upon the journey of becoming Aspirational Towns. 4.49 Lakh people participated in this programme. 1,33,524 households were covered for door to door awareness drive under ban on single use plastic, 2,740 Street vendor licenses were issued and 5,002 individuals were covered under self-employment drive in the Urban Local Bodies. 38,973 golden cards were issued, 508 city plans were prepared; 53,923 Land Passbooks were issued and 2,649 inheritance mutation were done.
- i) As a part of outreach programme, 34 Hon'ble Union Minister's from various Ministries of Government of India visited in 17 districts of Jammu and Kashmir in 2022 for public interaction and gathering grass-root level feed-back on government policies. Interactions were held with representatives of Panchayati Raj Institutions, other important stakeholders from trade, industry etc; which is expected to improve governance and implementation of various developmental schemes and initiatives in Jammu and Kashmir.
- j) "Aspirational Block Development Programme" has also been initiated for upliftment of backward blocks and Rs. 44 crore with Rs. 1 crore per block have been provided
- k) Jammu and Kashmir is 1<sup>st</sup> amongst Union territories to fully implement e-office in 300+ offices with highest 97 % disposal rate. The practice of Darbar Move has ended.

- l) e-GRAS has been launched to facilitate payment of taxes and user charges electronically without visiting to the treasuries and banks. The portals of revenue collecting departments are in the process of integration with e-GRAS system.
- m) Jammu and Kashmir is the first Union Territory to launch online e-Audit Application for conduct of statutory audit of departments. The e-Audit Portal is an integrated single platform tool for access of financial information of departments through BEAMS/JKPAYSYS on real time basis.
- n) Government of Jammu and Kashmir has introduced E-HRMS, a unified dashboard, wherein vital service related details like appointment, postings, promotions, monthly salary slips, income tax deductions and provident fund can be accessed. More than 3.65 lakh employees have been registered on this portal which has improved transparency in maintaining the service records of the employees. An online portal for filing the Property Return Statement for employees has been developed. Around 3.50 lakh employees have filed their property returns through this online portal.
- o) Social Security schemes and other flagship beneficiary schemes will be saturated for Kashmiri Migrants under special Lieutenant Governor's Camps. Under Jan Abhiyan such special Lieutenant Governor's camps are being held at different locations for enrolment of Kashmiri Migrants under various beneficiary oriented schemes. Further providing of security to Kashmiri Migrant Employees is the prime concern of the Government and to address the same, all the migrant employees have been suitably posted at secured places.

## 8. **Accelerating Development:**

- (a) Against 9229 works/projects under various sectors/ schemes completed in 2018-19, 12637 works / projects were completed in 2019-20. 21943 works/projects have been completed in 2020-21. During the financial year 2021-22; 50,627 works/ projects under different sectors/ schemes

have been completed. This shows that the pace of development has increased manifold and during current financial year 2022-23 around 70,000 works/projects are likely to be completed.

- (b) The pace of execution of projects under Prime Ministers Development Package (PMDP) has been accelerated. Expenditure has reached to Rs. 39133 crore. 29 Projects have been completed / substantially completed and another 03 projects are likely to be completed by end of the current financial year.
- (c) Government of Jammu and Kashmir is taking concerted efforts to accelerate the pace of development. The road connectivity is extremely essential for the development of any region. I must inform this August House that till the year 2018, on an average, 1500 to 1600 Km of road length used to be constructed each year in Jammu & Kashmir. The same has now more than doubled to 3200 kilometres. Union Territory of Jammu & Kashmir is macadamizing more than 12 Km road length every day. Jammu and Kashmir is marching ahead with its ambition of road to every village.
- (d) 8.45 Km Qazigund-Banihal Tunnel at a cost of Rs 3,117 crore has been completed, which has now reduced travel time between Srinagar and Jammu from 10 hours to 5 hours.
- (e) Kashmir is likely to be connected to rest of the country through rail network by the end of the year 2023.
- (f) Road infrastructure by way of construction of mega highways and tunnel projects is in progress. A number of highway projects are presently under execution. Work on Srinagar-Jammu National Highway is being completed in next 2-3 years bringing much respite for the people of Jammu & Kashmir.
- (g) The work on 6.5 Km Z-Morh Tunnel on Srinagar- Sonamarg Road is going on at the brisk pace and will be completed during the current financial year at a cost of Rs. 2,378 crore, which will provide an opportunity for tourists to visit the beautiful place of Sonamarg in winter as well.

- (h) The construction of 135 Km stretch of six-lane Delhi-Amritsar Katra Expressway falling in Jammu & Kashmir has commenced. This will reduce the travel time to Shri Mata Vaishno Devi Shrine to 6 hours only.
- (i) Construction of 14.15 km two-lane bi-directional Zojila Tunnel with 14.20 km parallel escape tunnel is in progress.
- (j) Construction of 4 tunnels (4.85 Km) on Akhnoor-Poonch section of NH 144A is in progress.
- (k) Construction of double laning of 35.38 Km on Akhnoor-Poonch road (NH-144A) is in progress.
- (l) The expansion of Jammu and Srinagar Airports is under progress.
- (m) Construction work of AIIMS at Vijaypur, Jammu and AIIMS at Awantipora, Kashmir is proceeding at a fast pace.
- (n) 07 New Government Medical Colleges are being established and 15 Nursing Colleges will be made operational.
- (o) Two State Cancer Institutes will be made fully functional. Rs 881 crore are being spent on rebuilding/upgrading of 140 health institutions to be completed during this year.
- (p) Intake capacity of MBBS has increased from 500 to 1100 seats and PG seats from 513 to 593.
- (q) Under Jammu & Kashmir "SEHAT" health insurance scheme, in convergence with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), the registration of beneficiaries has reached to 83.97%.
- (r) Power Generation capacity will be doubled in 3 years. In last 2 years alone, projects of more than 3000 MW capacity have been revived and put on track. Work on 1000 MW Pakal Dul and 624 MW Kiru is in full swing. 850 MW Ratle has been awarded. Pre-construction activities have been initiated for 1856 MW Sawalkote project by NHPC.



- (s) Indian Institute of Technology, Jammu is functioning from its own campus and Indian Institute of Management, Jammu to move to its campus this year.
- (t) 213 projects with a financial assistance of 250 Million USD from World Bank were under taken by Jehlum Tawi Flood Recovery Project Organization. 159 projects have been already completed and 54 projects are in the advanced stage of execution.
- (u) Under initiative of "Har Gaon Ek Amrit Sarovar" 4041 Amrit Sarovars have been identified, out of which 2420 have been completed and remaining will be completed before 15<sup>th</sup> of August 2023.
- (v) In preparation for G20 summit meetings, the Government of Jammu and Kashmir will undertake development of key infrastructure projects under road, urban and tourism sectors.
- (w) A special programme is being launched during 2023-24 for implementation of all components of action plan of two National Conferences of Chief Secretaries.

## 9. **Industrial Development:**

- (a) The focus of the Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021-30 is to attract new investment, creation of employment opportunities for youth, development of backward regions and nurturing of existing industrial units. As a first step, Jammu and Kashmir Industrial Land Allotment Policy 2021-30, Jammu and Kashmir Private Industrial Estate Development Policy 2021-30, Jammu and Kashmir Wool Processing, Handicrafts and Handloom Policy 2020, have been notified.
- (b) Credit Card Scheme for Artisans and Weavers is being implemented with interest subvention of 7%.
- (c) Karkhandar Scheme announced last year is being implemented to provide fresh impetus to the craft industry.

- (d) Steps are being taken to promote Industrial Development and investment proposal worth Rs. 64,058 crore have been received involving land bank of 47,092 kanals thereby having a potential to generate employment for 2,93,689 youth.
- (e) During 2022-23, till January, 2023 an investment of Rs 1547.87 crore has been received. The investment during the last 10 months of current financial year is highest ever compared to any previous financial years.
- (f) In the last three years, 500 start ups have come up which have ushered a new social revolution.
- (g) Government is committed to provide training, design, technology inputs like GI tag and such other infrastructural support as are required for quality, branding and boosting global demand for handicraft products of Jammu & Kashmir.

#### 10. **Employment:**

- (a) Largest ever recruitment drive has been initiated in Jammu & Kashmir. 100% recruitment is based on Merit. Totally fair, transparent, and fast-track process is adopted for recruitment. Interviews upto Pay Level – 5 have been dispensed.
- (b) 33426 Posts have been referred to recruiting agencies, against which 25450 selections have been made including 2436 selections of Jammu and Kashmir Bank Limited. Remaining are under process for fast track recruitment.
- (c) Employment generation is also encouraged through a number of self-employment schemes like Mumkin and Tejaswani under Mission Youth, Rural Livelihood Mission, Himayat, Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP), J&K Rural Employment Generation Programme (J&KREGP), J&K Urban Employment Generation Programme (J&KUEGP), Women Entrepreneurship Programme, AVSAR etc. 2,02,749 youth have been covered under various self-employment schemes in 2022-23 and target is to cover 2,37,000 youth by end of March, 2023.

(d) Jammu and Kashmir has correspondingly higher labour force participation which is more than the national average. The wage employment has been almost saturated.

#### 11. **State of Economy:**

Despite odds, Jammu and Kashmir has sustained the pace of development and expeditiously managed the expenditure both under revenue and development side. The overall GSDP growth during financial year 2021-22 has been 14.64% (1<sup>st</sup> Revised) as compared to financial year 2020-21. The sectoral breakup shows resilience in the economy.

<b>Primary Sector:</b>	<b>6.58%</b>
<b>Secondary Sector:</b>	<b>8.59%</b>
<b>Tertiary Sector:</b>	<b>18.69%</b>

The economy is on right track and government is focusing on equitable growth in all the sectors of the economy. The economy is expected to grow at 10% and there has been significant growth in collections under GST, Excise and Stamp Duty. The GST collection is Rs 6666.04 crore upto February, 2023; which has shown a growth of 14.64 percent over the same period of previous financial year 2021-22. The MST collection is Rs. 1444.45 crore upto ending February, 2023. The stamp collection is Rs. 438.88 crore upto February, 2023 against Rs 401.44 crore during the last financial year 2021-22; showing a growth of 9.33 percent. The excise collection has been Rs 1658.35 crore upto ending February, 2023 during current financial year 2022-23 against 1443.07 crore in the same period during the last financial year 2021-22; registering a growth of 14.92 %. The overall tax collection has shown significant growth and resilience.

12. This season we have also seen a good flow of tourist and over 1.88 core tourists visited Jammu and Kashmir during previous year upto December, 2022. Out of this 26.73 lakh tourists visited Kashmir which is more than double than the previous highest of 12.99 lakh in the year 2016. For the first time, the world famous Gulmarg Gondola has realized revenue of about Rs. 100 crore.

13. Exports of dry & fresh fruits is picking up and by end of February, 2023 about 18.15 lakh metric tons have been exported.

**14. Financial Inclusion:**

(a) Under Atma Nirbar Bharat Abhiyan, 65,907 borrowers have been benefitted under Guaranteed Emergency Credit Line GECL (1.0, 2.0 & 3.0) involving Rs 2488.04 crore and free rice was provided to 16,49,706 families and pulses to 16,97,820 families. Special credit facility for street vendors with an initial working capital of Rs 10000, Rs 20000 & Rs 50000 has been disbursed to 20,596 beneficiaries under PM-SVANidhi Scheme. Rs 5794.12 crore credit has been provided to 7,86,077 KCC (Crop) account holders and Rs 825.86 crore to 1,54,604 KCC-Animal Husbandry & Fisheries (AH&F) account holders. Rs 5251.22 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY), loan has been disbursed to 2,42,828 beneficiaries.

(b) Over 50,000 units have been set up with credit of around Rs 1,018 crore from banks, providing employment to nearly 75,000 youth identified during fourth phase of "Back to Village Programme" and second phase of "My Town My Pride Programme".

**15. Direct Benefit Transfers:**

(a) All the individual beneficiary schemes have been almost saturated and we are committed to achieve 100% saturation in respect of these schemes along with 100% Aadhar seeding. Around Rs 1378 crore have been disbursed to more than 39 Lakh beneficiaries through DBT so far during 2022-23.

(b) In the last one year, Jammu and Kashmir recorded 11 Lakh e-transactions per day, which is about 48,000 e-transactions per hour.

**16. Budget 2023-24:**

16.1 The priorities for the Budget of the Union Territory of Jammu & Kashmir for the year 2023-24 shall be based on the underlying themes:

- i. Good Governance
- ii. Strengthening Grass-root Democracy

- iii. Promoting Sustainable Agriculture
- iv. Facilitating Investment & Industrial Growth.
- v. Employment Generation.
- vi. Accelerated Development & Inclusive Growth.
- vii. Women Empowerment.
- viii. Social Inclusion.
- ix. Doubling GDP within five years.

16.2 The budget 2023-24 for Jammu and Kashmir shall again cross Rs 1 lakh crore mark, an indicator of our commitment to make Jammu and Kashmir a model of development. The total budget estimates for the fiscal is Rs. 1,18,500 crore, of which developmental expenditure is of the order of Rs. 41,491 crore.

16.3 The capital component of the budget has increased substantially. The expected revenue receipts are Rs 1,06,061 crore whereas Revenue expenditure is expected to be Rs 77,009 crore, thereby making available revenue surplus for capital expenditure to the tune of Rs 29,052 crore.

16.4 The Capital Receipts are projected at Rs 12,439 crore and Capital Expenditure is expected to the tune of Rs 41,491 crore. 35% of the earmarked Budget shall be spent on development and infrastructure projects.

## **17. Socio-Economic Development:**

### **17.1 Agriculture, Horticulture and Sericulture Sector:**

- (a) The Jammu and Kashmir Holistic Agriculture Development Plan will be rolled out which will make horizontal change in the agriculture sector in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Under this plan, 29 projects have been approved with an outlay of Rs 5,012 crore over a period of next five years. This will transform the agriculture economy of Jammu and Kashmir putting it on a new

trajectory of growth, doubling the output of sectors, boosting exports and making the sectors sustainable and commercially viable. It will herald a new phase of farming prosperity and rural livelihood security in Jammu and Kashmir and create additional job opportunities to 2,87,910 people in agriculture and allied sectors. 18,861 new business enterprises will be created over the period of next five years.

- (b) Under this Holistic Agriculture Development Plan; 67,000 Metric Ton Controlled Atmosphere (CA) storage space will be created with full value chain and aggregation network. Honey production will be tripled and Cocoon production will be increased from 700 Metric Ton to 1,350 Metric Ton over the period of next five years.
- (c) Market-led production of food grains and high value crops will be grown in non-traditional areas.
- (d) Farm power to be raised to 2.5 KW/hectare to minimize human drudgeries, reduction in cost of cultivation and ensure timely action and increase in production and productivity.
- (e) The earnings from export of speciality products like Basmati, Rajmash, Kala Zeera, Mushkibudji, Saffron and honey will also increase.
- (f) The area under assured irrigation will also expand from 30% to 40%.
- (g) The gross cropped area will register rise from present 11.34 lakh Hectare to 12.50 Lakh Hectare by way of increased cropping intensity (Double/Triple cropping).
- (h) Production and post-harvest losses will be reduced from 20-25% to 15-18% through post-harvest management initiatives envisaged under various schemes.
- (i) Providing of Silk-Worm Seeds of improved races procured from National Silkworm Seed Organization (NSSO) to the farmers for conducting silkworm rearing. The seed to the farmers is supplied on highly subsidized rates by the Department.

- (j) 200 Farmers to be provided rearing appliances to assist in rearing of cocoons on scientific lines for increasing cocoon yield.
- (k) Construction of Chawki & Rearing Centre for incubation of Silk Worm Seeds for distribution of chawki reared worms to the rearers.
- (l) Production of Pheromone baited traps for integrated pest management in fruit plants.
- (m) Internet of Things (IoT) and robotics for automation in Agriculture.
- (n) Packaging units for food items like Gucchi, Rajmash & other local forests/ Agriculture produce at Bholderwah, District Doda.
- (o) Establishment of cedar wood oil extraction and packaging unit at Bholderwah, District Doda.
- (p) International Fund for Agricultural Development (IFAD) project to be taken for implementation during 2023-24 with funding under multilateral agency and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
- (q) Production of designer plants for promotion of High Density Plantation and Rejuvenation of Orchards.
- (r) Strengthening Agricultural Marketing in Jammu and Kashmir by providing platform to the growers for marketing of horticulture produce, buyer-seller linkages for direct contact for sale and purchase of horticulture produce and ensuring more profits to farmers/ growers.
- (s) Subsidy Support under the scheme PARVAZ for air transportation of perishable fruits like Cherry, Strawberry, Plum, Pear, Peach, Litchi and exotic/ organic vegetables.
- (t) 2000 Metric Ton capacity cold store at Narwal Jammu and 2,500 Metric Ton capacity cold store at Mazbugh, Sopore to be established.
- (u) GI tagging of local produce to authenticate and promote fruits of the Union Territory.

- (v) Support under development of High Density Plantation Nurseries Scheme in public & private sector for increasing area under Mango and Citrus plantations in Hectare, Kiwi fruit plantations in Hectare, Apple, Walnut and Stone fruit plantations in Hectare.

**For Agriculture and Horticulture Sectors, an allocation of about Rs. 2526.74 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 1239.45 crore more than previous year's budget allocation.**

### **17.2 Animal, Sheep Husbandry and Fisheries Sector:**

- (a) Under the Holistic Agriculture Development Plan milk output will increase by 75% and milk entering processing chain will be tripled over the period of next five years. Jammu and Kashmir will become self-reliant in mutton and wool production.
- (b) The Trout and Carp production to be doubled over the next five years.
- (c) Increase in milk production from 25 to 45 Lakh Metric Ton alongwith increase in milk collection/chilling from 2.0 to 8.5 lakh litres per day (LLPD) and around 3.6 Thousand Metric Ton of value added products will enter the market over the next five years.
- (d) Income enhancement of sheep rearers/breeders for greater livelihood security. Employment and income generation boost to wool processing industries.
- (e) Towards self-sufficiency in fodder development for supporting burgeoning livestock population and to narrow down the fodder deficit of Union Territory by 80%.

**For Animal, Sheep Husbandry and Fisheries Sectors, an allocation of about Rs. 629.70 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 267.84 crore more than previous year's budget allocation.**



### 17.3 Health and wellness:

- i. The Health & Medical Education Department is regularly focusing on improved public service delivery mechanism and meeting Indian Public Health Standard (IPHS) norms through extended outreach for health care of masses and improving patient experience. The stakeholder's feedback is assessed and ranking of health facilities is done regularly.
- ii. Operationalization of modern Drug Testing Laboratory at Kathua.
- iii. Operationalization of Cancer Institute, Jammu.
- iv. Establishment & operationalization of Cathlabs at Government Medical College Anantnag.
- v. Attaining Tuberculosis (TB) free status for Districts of Anantnag, Kulgam, Pulwama, Shopian and Kupwara.
- vi. Saturation in operationalization of all Health & Wellness Centres.
- vii. Training on Yoga and Wellness for 1000 Ayush Paramedics for extended outreach of Yoga among community under Karamyogi campaign.
- viii. Introduction of Robotic Surgery at Government Medical College, Srinagar/ Jammu.
- ix. Establishment of Control and command centre for improved patient care at Government Medical College Jammu & Government Medical College Baramulla.
- x. Strengthening of trauma care facilities in accident prone districts through optimization of infrastructure, manpower and provisioning of high-tech equipment's for emergency diagnosis especially in areas like Doda/Kishtwar/Ramban.
- xi. Establishment of 25 Urban Health & Wellness Centres, 57 Block Public Health Units, 04 District Integrated Public Health Labs & One 50 Bedded Critical Care Block.

- xii. All facilities to be covered under Kayakalap.
- xiii. Extension of telemedicine services for Intensive Care Units.
- xiv. Extension of modules under Health Management Information System (HMIS) for improving Public Health Delivery Mechanism and Patient Records under Ayushman Bharat Health Account (ABHA).
- xv. Tribal Accredited Social Health Activists (ASHAs) and Mobile Medical Units for tribal areas.
- xvi. Effective management for day care chemotherapy in all Districts.
- xvii. Up-Scaling/Updation of OPD/IPD facilities under Nasha Mukh Abhiyan.
- xviii. Reduction in C-Section deliveries by at least 20%.
- xix. 100% screening of school children and other sections of the population.
- xx. Implementation of Tele Mental Health Assistance and Networking Across States (Tele-MANAS).
- xxi. Implementation of e-sanjeevani.
- xxii. Establishment of medicine delivery system with introduction of drones for essential supplies/medicine on pilot basis and creation of drone stations.
- xxiii. Implementation of tele Out-patient Department (tele-OPD).
- xxiv. Unified Digi surveillance system in health sector.
- xxv. Health screening at panchayat level.
- xxvi. 100% screening/ surveillance of Non-communicable diseases (NCD) and other diseases.
- xxvii. Early identification of high risk pregnancies & focus on postnatal care.
- xxviii. Full (100%) immunization coverage.
- xxix. Reinforce Anaemia Mukh Jammu and Kashmir.

- xxx. Radiotherapy equipment to be made available at all the Medical Colleges.
- xxxi. All 7 Medical Colleges to provide facilities for treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), ST Elevated Myocardial Infarcted (STEMI) stroke and chemotherapy.

**For Health and Medical Education Sector, an allocation of about Rs. 2097.53 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 214.97 crore more than the previous year's budget allocation.**

#### **17.4 Rural Development:**

- (a) The villages will be developed as Model Villages with all the required amenities. All villages will be declared Open Defecation Free plus status (ODF plus) with implementation of all the components of Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G).
- (b) Launch of HIMAYAT 2.0 with renewed focus on employment oriented trades for training and convergence of skill related infrastructure across the Departments like Skill Development, Mission Youth Industries & Commerce, School Education, Agriculture etc.
- (c) Under NRLM-UMEED, Jammu & Kashmir Rural Livelihoods Mission (JKRLM) will focus on gender issues by forming Gender Forums at District, Block and Panchayat Level for registration of complaints for their redressal and service sector projects. 10,000 additional Self Help Groups (SHGs) will be formed taking total number to 1,00,000 in Jammu and Kashmir.
- (d) 1500 new Panchayat Ghars will be constructed under Rastriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) within the initiative of "Har Panchayat-Panchayat Ghar". 100% Internet connectivity will be provided to the Panchayat Ghars across the Union Territory.

- (e) More than 3 lakh mandays of training of PRI members to be carried out under RGSA along with enhanced budget for exposure visits to other progressive States.
- (f) 40,000 houses will be constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) scheme across Jammu & Kashmir for house less families.
- (g) Construction of 87250 Individual Household Latrines (IHHLs) and construction of 2500 Community Sanitary Complexes (CSCs).
- (h) More than 2080 villages to have provision for Solid Waste and liquid waste management along with provision for faecal sludge management.
- (i) More than 2080 villages to become clean and litter free and these villages will be Plastic free with provisions for grey water.
- (j) PRI members accommodation will be created using low cost sustainable technologies.
- (k) Under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 400 lakh mandays will be generated under the scheme and it will be fully saturated with issuance of 100% online job cards.

**For Rural Sector, an allocation of about Rs. 4169.26 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24.**

### **17.5 Power Sector:**

- (a) Improvement in daily hours of power supply with urban at 24 hours & rural at 22 hours.
- (b) Reduction in transformer damage rate, drop in Transmission & Distribution/Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses.
- (c) 60% of energy consumed is targeted to be metered via smart meters by April 2023 and 100% consumers to be metered with smart meters by 2024-25.

- (d) Renovation and modernization works to be undertaken at existing 220/132 KV Grid Sub Stations and protection/ replacement works at critical towers and insertion of new towers.
- (e) Grid Connectivity of Gurez for reliable power supply to this border area and adjoining areas.
- (f) Underground cabling through Z-Morh Tunnel for providing 24x7 Power supply to Sonamarg during winters.
- (g) Underground cabling at Nunwan for reliable power supply to Holy Cave of Shri Amar Nath Ji.
- (h) Construction for 540 MW Kwar Hydro Electric Power project to be initiated during 2023-24.
- (i) To enhance the capacity of new 220 KV & 132 KV Grid Sub-Stations by 575 MVA and 100 MVA and existing 220 KV & 132 KV Grid Sub-Stations by 725 MVA and 754 MVA.
- (j) Laying of transmission lines at 220 KV and 132 KV level by way of HTLS Conductor and normal ACSR conductors on critical lines. This will increase current carrying capacity by almost two times, which in-turn will lead to better utilization of existing Grid Stations. Besides, it will ensure reliable and smooth power supply.
- (k) Addition to length of LT/HT network by 1324.073 Km.

**For Power Sector, an allocation of about Rs. 1964.90 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24.**

#### **17.6 Tourism and Culture:**

- (a) As a "Tourism Mission" initiative 75 new destination, 75 Sufi/religious sites, 75 new cultural/heritage sites and 75 new tracks are being developed and opened up so that the economic gain of tourism industry trickle down to far off and hitherto unexplored areas. The promotion of Film Tourism will be important component of the "Tourism Mission" for the year 2023-24.

- (b) Caravan Tourism, a new tourism vertical to be opened which will provide tourists a new activity and aid in promoting unexplored areas and off-beat destinations with minimal infrastructure projects. Eco-mobility facility to be created at Sonamarg, so that tourist can visit Thajiwas Glacier without effecting the environment.
- (c) To add new vertical in tourism sector, Vista Dome Services to be operationalized on Baramulla-Banihal Railway stretch in collaboration with Railways.
- (d) Road shows/events /festivals will be conducted at Union Territory, National and International level to promote tourism.
- (e) Development of water parks at twin cities of Jammu & Srinagar.
- (f) Upgradation of boat club cum water sports centre at Wular Lake to introduce water sport activities in Wular and Mansabal Lakes. Facilities will be created for water based activities at Dal Lake, Mansar Lake and Bhagliyar dam site.
- (g) Athwajan Park, Srinagar and Khadinayar Park, Baramulla to be developed for recreational activities, adventure zones and children playing zones.
- (h) Sporting activities to be conducted at new destinations like Sonamarg, Doodpathri Yusmarg, Bhaderwah & Patnitop besides at Gulmarg.
- (i) Tourist Information Centres to be established at Baltal, Chandanwari, newly constructed Tunnel at Qazigund, Teetwal and Gurez for catering pilgrimage tourism during Shri Amar Nath Ji Yatra and promotion of Border Tourism.
- (j) Promotion of traditional & cultural festivals across the Union Territory.
- (k) Women guides to be encouraged at tourist places.
- (l) Culture Centres to be established at Bandipora, Shopian, Anantnag, Kishtwar, Udhampur, Kathua, Jammu and Poonch.

- (m) All the public libraries of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be transformed into e-Libraries.
- (n) Two old heritage sites at Shergari Complex and Old Shri Pratap Singh (SPS) Museum Srinagar to be restored and conserved under conservation of heritage sites programme.
- (o) Abhinav Theatre at Jammu and Tagore Hall at Srinagar to be repaired, restored and upgraded.
- (p) Talent hunt activities to be conducted.
- (q) New "Art Museum" at stone building, Old Secretariat, Srinagar to be constructed.
- (r) Historical fort at Samba, Narastan Monument at Tral, Pulwama, Hariparbat Fort at Srinagar and General Zorawar Singh Palace at Reasi to be refurbished for encouraging tourism.

**For Tourism and Culture sectors, an allocation of about Rs 457.39 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 54.31 crore more than previous year's budget allocation.**

## **17.7 Jal Shakti Department:**

### **I. PHE Sector:**

- (a) All 18.36 Lakh households of Jammu and Kashmir to have Functional Household Tap connections by 2023-24. Every household to be provided drinking water with minimum 55 litre per capita per day (LPCD) and of prescribed quality (confirming to BIS 10500) on regular, long term and sustainable basis.
- (b) 60 water supply schemes are likely to be completed during 2023-24.
- (c) 100% Radio-Frequency Identification (RFID) based tanker service to be introduced in rural areas.

- (d) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accreditation for 20 Labs.
- (e) Digitalization of consumer records and implementation of online billing system in entire Jammu and Kashmir.

## **II. Irrigation & Flood Control Sector:**

- (a) Construction of Tawi Barrage to be completed during 2023-24.
- (b) Timely desilting of irrigation canals.
- (c) Completion of Hokarsar wetland sluice gates for maintaining optimal water depth.
- (d) Implementation of part-B of "Jhelum Flood Management" for increasing its carrying capacity.

**For Jal Shakti Department, an allocation of Rs. 7161 crore has been made under Capital Expenditure for 2023-24, which is Rs. 3191 crore more the previous year's budget allocation.**

## **17.8 Housing and Urban Development Sector:**

- (a) 50,000 Households are likely to be provided with water tap connections during 2023-24, under universal coverage of water supply to Urban Local Bodies (ULBs).
- (b) Sewage management of Dal Lake, Polluted river stretch of Anantnag and the remaining towns are being covered under septage management.
- (c) 13.60 Million Litres per Day (MLD) capacity to be added under project Devika.
- (d) Sewage Treatment Plants (STPs) of 89.83 MLD capacity to be installed in phased manner, which is likely to benefit 6,20,565 souls.
- (e) Under AMRUT-2.0 all the identified water bodies in the ULBs are being rejuvenated in phased manner, besides, river fronts viz. Jhelum River Front in Srinagar & Tawi River Front in Jammu are being developed through Smart Cities Mission and will be completed during 2023-24.



- (f) Open Defecation Free (ODF) has been achieved in all 78 ULBs of Union Territory and 16 ULBs are ODF+. 100% ODF+ to be achieved in all ULBs during 2023-24.
- (g) Under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U); 18,934 dwelling units to be completed during 2023-24 under Beneficiary Led Construction (BLC) component.
- (h) For improving access to rental housing for urban poor migrants, 336 flats at Sunjwan, Jammu are being upgraded and will be provided to the urban poor/migrants during 2023-24.
- (i) Mass Housing/New Townships/Affordable Housing for Economically Weaker Section/Low Income Group/Middle Income Group to be developed at Gund-a-Raksha & Chatterhama, Srinagar and Kot Bhalwal at Jammu.
- (j) 130 projects are expected to be completed under "Smart Cities Mission" during 2023-24. This will have improved infrastructure, Integration of technologies for smart governance, smart mobility, smart health centers, development of green spaces, street lightening and promotion of heritage.
- (k) Elevated light Metro Rail in both the capital cities of Jammu and Srinagar is expected to be rolled out during 2023-24 which will help the commuters in both the capital cities and also help in traffic decongestion.
- (l) An Inter Model Station (IMS) at Katra as a terminal infrastructure to integrate various transportation modes such as Rail, Road and Air to be developed during 2023-24.
- (m) Promoting circular economy.
- (n) Scheme for disposal of electronic waste to be introduced.
- (o) Introduction of policy for city mobility plans.

- (p) Establishment of "Ladies Haat" and Ladies exclusively markets at Srinagar, Jammu and other major towns.
- (q) Creation of Ekta Malls.

**For Housing and Urban Development Sector, an allocation of about Rs. 2928.04 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 674.78 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **17.9 Education Sector:**

### **I School Education:**

- (a) Intensive enrolment drive under "Aao School Chalein" to be continued for increasing gross enrollment ratio.
- (b) 2000 Kindergartens are proposed to be established during 2023-24 for providing quality pre-primary education.
- (c) 10 residential schools to be established during 2023-24 with preference to tribal students and students from weaker sections for accommodating in these residential schools on merit for providing them quality education.
- (d) 1000 smart classrooms with LCD & having high speed internet connectivity in a class to be established in High & Higher Secondary Schools for imparting quality education to students.
- (e) Sports infrastructure including change rooms for players to be provided to 100 High and Higher Secondary schools.
- (f) 500 additional class rooms to be provided in high and higher Secondary Schools benefitting more than 20,000 students.
- (g) Free text books to be provided to all the students of elementary classes.
- (h) Free uniform to be provided to all the elementary students belonging to weaker sections.

- (i) Drinking water facility and gender based toilet facility to be made available in all the Schools.
- (j) 500 schools to be provided ICT Labs and 100 Vocational Labs to be established in the Schools.
- (k) Under Infrastructure/Quality Education, one residential school each in Baramulla, Shopian, Kishtwar and Rajouri Districts will be established to provide education to the wards of migratory people.
- (l) 188 Virtual Reality Labs to be established in Jammu and Kashmir (One Lab in each Zone) to inculcate the scientific temper among students.
- (m) 40 Robotic Labs to be established (Two Labs in each District) to help in improving schools digital equity, literacy and economic development besides, new teaching methodologies.
- (n) Yoga training for all the students to keep them fit to be introduced as part of co-curricular activities.

## **II Higher Education:**

- (a) Jammu and Kashmir is one of the front runner in adoption of National Education Policy (NEP) and will be fully implemented in the year 2023-24.
- (b) NAAC accreditation of 32 colleges will be completed in 2023-24.
- (c) Samarth "ERP eGov Suite", will be fully implemented in 2023-24 with an aim at managing HRM, estate and inventory of Government Colleges and creating a centralized admission with student life cycle.
- (d) Higher Education Council to be made functional during 2023-24.
- (e) 08 college buildings and 04 hostel buildings likely to be completed in 2023-24
- (f) 04 auditoriums and 04 multipurpose halls likely to be completed in 2023-24
- (g) 02 library blocks likely to be completed in 2023-24.

**For School and Higher Education Sector, an allocation of about Rs 1521.87 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 193.61 crore more than the previous year's budget allocation.**

#### 17.10 Road Connectivity (Roads & Bridges):

- (a) Overall, 6000 Kilometers of black-topping of roads is expected to be achieved during 2023-24 under all Schemes.
- (b) 253 new projects at an estimated cost of Rs 1292 crore have been prioritized to be sanctioned under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)-XXVIII with NABARD funding and will be taken for execution during 2023-24.
- (c) Safety audit of bridges having completed 20 years has been completed during 2022-23. Safety audit for the bridges having completed 10 years to be conducted during 2023-24.
- (d) Efforts are being put on maintenance of road/bridge assets and also for road safety measures.
- (e) Construction of 60 ongoing bridges sanctioned under different schemes to be completed during 2023-24.
- (f) "Passing Bays" on all major roads to be constructed during 2023-24.
- (g) PMGSY-III works to be started during 2023-24.

**For Road and Bridge Sector, an allocation of about Rs 4062.87 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 98.99 crore more than the previous year's budget allocation.**

#### 17.11 Industries and Commerce:

- (a) 29 major projects have been identified for development of new industrial estates during 2023-24.
- (b) The investment proposals for setting up of Medicities in Jammu and Srinagar have been received for creation of health infrastructure in private sector. Medicities at Sempora, Srinagar and Meeran Sahib, Jammu are being established to provide better health care facilities.

- (c) The main aim of "One District One Product" is to promote local product for export. In this behalf district Srinagar & Jammu have been selected amongst the 75 districts across India for export of local products.
- (d) 1500 units under Jammu and Kashmir Rural Employment Generation Programme (J&KREGP) are targeted to be established in 2023-24 involving margin money of 30 crore with employment to 9000 persons.
- (e) Exhibitions to be conducted for showcasing of industrial potential.
- (f) Workshops on capacity building/start-up promotion to be organized.
- (g) Providing of turnover incentives to boost industrial Development for entailing increase in employment.
- (h) Introduction of quality certification with branding under Handloom and Handicraft sector.
- (i) Popularization of local products.
- (j) Reducing compliances on "Ease of Living" and "Ease of Doing Business".
- (k) Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) development policy to be notified.
- (l) Samadhaan 2.0 to be implemented.
- (m) Tie-up of MSME with e-commerce platforms to be taken.
- (n) Policy framework to support private investment to be introduced.
- (o) Implementation of unified logistic interface platform.
- (p) Creation of export hubs.
- (q) Adoption of plug and play model for key development sectors including manufacturing sector.

**For Industries and Commerce Sector, an allocation of about Rs 741.79 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 283.40 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **18. Social Security Sector:**

- (a) Biometric Attendance System to be installed at all the Anganwadi Centres in phased manner.
- (b) Scholarship to 124300, Pre-Matric students (1<sup>st</sup>-8<sup>th</sup>) belonging to categories of Scheduled Caste/Other Backward Classes/Economically Backward Classes/Physically Challenged Persons will be covered.
- (c) All the Child Care Institutions to be developed on modern pattern with best living conditions for the inmates. 1700 inmates in 19 Bal Ashrams and 12 Nari Niketans to be covered.
- (d) District Disability Rehabilitation Centers (DDRC) to be established in all 20 districts.
- (e) Creation of Hub for Empowerment of Women (HEW) - Mahila Shakti Kendras
- (f) Establishment of GPS enabled women helpline.
- (g) Construction of working women hostels.
- (h) Training for specially abled persons.

**For Social Security Sector, an allocation of about Rs 98.92 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24.**

## **19. Tribal Welfare:**

- (a) 24 Scheduled Tribe & Gujjar /Bakerwal Hostels to be completed.
- (b) 07 Transit Accommodations for nomadic population are targeted to be completed.
- (c) Milk villages and smart schools will be established for tribal population.
- (d) Creation of market linkage for Tribal products like milk, mutton, sheep wool, leather etc.

- (e) Transport facilities are being made available to tribal families for the seasonal migration of their goods and cattle.
- (f) Tracking of educational, healthcare and economic status of nomadic population.

**For Tribal Affairs, an allocation of about Rs 446.76 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 13.97 crore more than the previous year's budget allocation.**

**20. Relief & Rehabilitation of Kashmiri Migrants:**

- (a) Foundation stone has been laid for construction of 936 flats as transit accommodation for Kashmiri Pandit employees at Zewan, Srinagar under Prime Ministers Development Programme. 1984 Transit Accommodations for kashmiri migrant employees will be completed during 2023-24.
- (b) The remaining posts of 355 out of 6000 posts under PM-Package for kashmiri migrants to be filled during 2023-24.
- (c) The cash assistance and food grains for Kashmiri/Jammu migrants to continue under SRE.

**For above package, an allocation of about Rs. 1102 crore has been made for the year under Revenue & Capital Expenditure 2023-24, which is Rs. 267 crore more than the previous year.**

**21. Youth Empowerment, Employment and Entrepreneurship:**

- (a) Financial support through banks and Mission Youth to be provided to youth for undertaking self employment ventures.
- (b) Under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Jammu and Kashmir Rural Employment Generation Programme (J&KREGP) & Jammu and Kashmir Urban Employment Generation

Programme (J&KUEGP) financial support in the shape of margin money will be provided for establishment of viable business units in rural & urban areas.

- (c) Under Self Employment Schemes viz Seed Capital Fund, Youth Startup Loan, National Minority Development Finance Corporation & Women Employment Programme a target of establishing 3200 units has been set for achieving employment for 8100 persons.
- (d) 40 job fairs including 02 mega job fairs, each at Jammu & Srinagar, to be organized.
- (e) 06 Model Career Centres to be established at Jammu, Srinagar, Anantnag, Shopian, Bandipora and Kupwara during 2023-24.
- (f) Establishment of international workforce mobility tracking system.
- (g) Skill development programme for overseas employment aspirants.
- (h) Youth Clubs to be made vibrant for up-skilling of youth.

## **22. Sports Initiatives:**

- (a) More and more sports activities in every nook and corner of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be conducted to engage 70 lakh youth in sports activities during 2023-24.
- (b) High Performance Centres to be established in Fencing, Wushu and Gymnastics.
- (c) Two Yoga Centres will be established one at Moulana Azad Stadium, Jammu and one at Bakshi Stadium, Srinagar.
- (d) Community participation in sports to be enhanced for developing vibrant sports ecosystem in the Union Territory.
- (e) 25 national events to be hosted in different sports events under "Ek Bharat Shreshta Bharat" Abhiyan.
- (f) Cricket, Football, Volleyball and Wushu academies to be set up for institutionalization of sports learning process.
- (g) Women participation in sports and para-athletics to be encouraged.



### **23. Skill Development:**

- (a) Up-Skilling of 60,000 Self Help Groups (SHGs) through customized courses and trainings in convergence with other departments.
- (b) Skilling scenario to be improved under Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) in 8 aspirational/border districts viz. Jammu, Poonch, Rajouri, Samba, Kathua, Baramulla, Bandipora and Kupwara.
- (c) Assessment/performance audit of all Industrial Training Institutes to be conducted.
- (d) Construction of Hostels in various Polytechnics and Industrial Training Institutes to be undertaken for providing boarding facilities to the trainees enrolled in various Polytechnics & Industrial Training Institutes across the Union Territory of Jammu and Kashmir.
- (e) Inclusive skill mapping of youth in Schools, Industrial Training Institutes, Polytechnics, Colleges and in tribal areas for disadvantaged youth to be conducted through UNICEF.
- (f) Construction of workshop blocks at Government Industrial Training Institute Handwara, Patan & Tangdhar to give a significant boost by imparting the technical and practical training skills to the trainees.
- (g) Creation of "Skill Hubs".
- (h) Training workshop on wheels to be introduced.
- (i) Dynamic District & Union Territory level skill development plan to be framed to encompass all skilling.
- (j) 'Skill Loans' from Jammu and Kashmir Bank for aspiring candidates.

**For Youth Empowerment, Employment, Entrepreneurship, skill Development and Sports Activities, an allocation of about Rs 396.63 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24.**

## **24. Forestry & Environment:**

- (a) Green Jammu and Kashmir drive to be carried out as an umbrella programme on afforestation. 1.50 crore saplings are targeted to be planted during 2023-24.
- (b) 4290 Village Panchayats to be covered under "Har Gaon Hariyali" plantation drive.
- (c) Under "One Beat Guard, One Village Programme" saplings and other planting material of fiber, food, fodder and timber species to be provided for planting in the village common land, kachharai and wasteland.
- (d) Conserving and promoting clean wetlands in forest/ protected areas.
- (e) Fodder production in forest areas to be enhanced.
- (f) All ponds in forest areas to be rejuvenated.
- (g) "Plastic Free Forests" initiative, to be launched as a campaign.
- (h) 6000 eco-clubs to be registered in schools.
- (i) De-silting of Wular Lake to be undertaken in a mission mode.
- (j) Jambu Zoo will be ready and thrown open to the people in 2023-24.
- (k) Pro Active and Responsive facilitation by Interactive and Virtuous Environmental Singlewindow Hub (PARIVESH) 2.0 to be implemented.

**For Forest, Ecology and Environment Sector, an allocation of about Rs. 207.75 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 68.52 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **25. Food Civil Supplies and Consumer Affairs:**

- (a) 100% distribution of ration to beneficiaries through Point of Sale (POS) machines.

- (b) Digitalization of store inventory and complete implementation of supply chain management.
- (c) Computerized weighing bridges to be put in place at Udhampur, Kishtwar, Ramban and Doda.
- (d) Working Standard Laboratories to be constructed at Bandipora, Shopian, Pulwama, Doda and Budgam.
- (e) Remodeling and face lifting of storage godowns at Nagrota, Rajouri, Khanabal, Kulgam and Beerwah.
- (f) Implementation of e-rupee transactions in deliverance of public distribution services.

**For Food Civil Supplies and Consumer Affairs, an allocation of about Rs. 390.87 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 21.49 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **26. Science & Technology:**

- (a) Under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Component "B", around 4000 Solar Agriculture Pumps will be installed during 2023-24.
- (b) Under PM-KUSUM Component "C", 5000 solar agriculture pumps will be taken up for installation during 2023-24 replacing the existing agriculture grid connected pumps.
- (c) Under Jammu Solar City Project, against total sanctioned target of 200 Megawatt Rooftop Solar Power Plants, around 80 Megawatts in aggregate to be achieved in 2023-24, covering around 20,000 households.
- (d) Under Rooftop Solar Power Plants for domestic sector funded by Ministry of New & Renewable Energy (MNRE), 3000 households will be covered to achieve installed capacity of 10 Megawatts during 2023-24.

- (e) Under Srinagar Smart City Project, around 3 Megawatt Rooftop Solar Power Plants will be installed in Srinagar city.
- (f) In first phase 50 buildings of Srinagar city and 20 other government buildings in different districts will be identified for providing grid connected rooftop solar power plants. The target will be to cover all the government buildings in a mission mode.
- (g) Around 72 Megawatts aggregate capacity of small hydro power projects ranging from 2-10 Megawatts to be allotted to IPPs during 2023-24.
- (h) Construction of Energy Bhawan at Channi Himmat, Jammu to be completed by end of 2023-24.
- (i) Innovation and dissemination center within the premises of Sub-Regional Science Centre, Lal Mandi, Srinagar to be established. This project will provide the impetus for creation of start-ups.
- (j) Demonstration farms of aromatic and medicinal plants to be established in various districts of the Union Territory.
- (k) Financial support to be provided to 100 Research and Development projects during 2023-24.
- (l) Process for establishment of Sub-Regional Science Centre, Jammu to be taken in collaboration with National Council of Science Museums, Ministry of Culture, Government of India.

**For Science & Technology, an allocation of Rs. 109.85 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 37.00 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **27. Cooperative Department:**

- (a) Restructuring of cooperative banks for enabling them to become profitable.
- (b) Core banking solution to be adopted by all the cooperative banks and starting of internet banking facility thereof.

- (c) Digitalization and compilation of data of all cooperative societies in Data Base Management System (DBMS).
- (d) 80 new food processing units to be setup and made functional. This will lead to growth in income of cooperatives and employment generation for youth.
- (e) Members of all "Artisan Cooperative Societies" to be saturated with Artisan Credit Cards.
- (f) Modernization of super bazars at Jammu, Srinagar, Anantnag, Baramulla & Budgam to be initiated and expediting construction of new cooperative super bazars at unexplored locations.
- (g) Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS), enabling their electronic linking with District Central Cooperative Banks (DCCBs).
- (h) Establishment of Women led Farmer Producer Organizations (FPOs).

**For Cooperatives, an allocation of Rs 25.00 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs. 10.00 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **28. Revenue Department**

- (a) Legacy data of last 20 years to be scanned, digitized and uploaded on National Generic Document Registration System (NGDRS) Portal/ UT Data Center.
- (b) Installation of Safety equipment's to prevent any damage to the record of registration documents for the Sub-Registrar offices.

**For Revenue Department, an allocation of Rs 59.50 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 12.65 crore more than the previous year's budget allocation.**

## **29. Transport Department:**

- (a) Scrapping policy of old vehicles in Transport Sector
- (b) Introduction of buses and pink taxis for women.
- (c) Women only bus drivers and conductors to be introduced.

**For Transport Department, an allocation of Rs 54.39 crore has been made under Capital Expenditure for the year 2023-24 which is Rs 9.39 crore more than the previous year's budget allocation**

## **30. Security related activities:**

- (a) Police Border posts to be created in all the border districts of the Jammu and Kashmir.
- (b) Crime Organization to be strengthened.
- (c) Construction and erection of dominant towers/jammers in Jails.
- (d) Construction of 02 hostels for wards of police martyrs.
- (e) Construction of police housing colonies across Jammu and Kashmir.
- (f) Up-gradation of Police Hospitals and Police Public Schools.
- (g) Construction of 02 hostels for wards of armed forces (Ex-Servicemen).
- (h) Modernization of existing Fire & Emergency Service Stations with procurement of latest technology driven instruments.
- (i) Construction of Narcotic Lab at Forensic Science Laboratory, Srinagar and Toxicology & Narcotic Lab at Forensic Science Laboratory, Jammu.
- (j) Construction and up-gradation of Physics & Ballistic Division at Forensic Science Laboratory, Jammu & Srinagar.

- (k) CCTV Surveillance system to be completed in all police stations and police posts.
- (l) CCTV cameras with command and control centre at public places.

**For Security Related Activities, an allocation of Rs 1,197 crore has been made for the year 2023-24.**

### **31. Financial Reforms/e-governance Initiatives:**

- (a) e-Office to be extended to all the offices of the Jammu and Kashmir.
- (b) e-billing system Public Works Online Management, Monitoring & Accounting System (PWOMAS) to be extended in all the Engineering Departments.
- (c) All the services and beneficiary-oriented scheme to be made 100% online.
- (d) PM-Gati Shakti to be fully implemented in all the Departments.
- (e) Universal transition to High Security Registration Plates and implementation of vehicle tracking platform to ensure continuous monitoring of all vehicles especially for safety of women.
- (f) Intelligent Ticketing Management System to be introduced in Jammu and Kashmir Road Transport Corporation.
- (g) Creation of online Census Management System by way of development of Mobile App.
- (h) Introduction of GST data Triangulation.
- (i) Creation of e-invoice system of GST.
- (j) Transition of GST-IN into GST-Prime.
- (k) Linking of e-way bill to FASTag & VAHAAN.
- (l) Creation of single unique helpline by IT Department.
- (m) Capacity building framework through inter- state knowledge exchange programme.

### **32. Supplementary Grant for the Current Financial Year 2022-23:**

- (a) The original grant for the financial year 2022-23 was Rs 1,12,950 crore. During the course of year from 1<sup>st</sup> April, 2022 to 31<sup>st</sup> March, 2023 an amount of Rs. 3711.7176 crore shall be withdrawn in excess of grant under the relevant Demands out of the Consolidated Fund of Union Territory of Jammu and Kashmir to defray expenses on services and purposes required during the period. This had been largely necessitated due to expenses on account of increase in salaries due to hike in DA @ 4%, annual increment, grant-in-aid, subsidy and other revenue expenses including pension and other retirement benefits, increased capital allocation under different sectors like Irrigation & Flood Control Projects, Tribal Sub Plan Projects, Skill Development Projects etc.
- (b) The Supplementary Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (01) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs. 3711.7176 crore from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the period w.e.f 1st April, 2022 to 31<sup>st</sup> March, 2023.

### **33. BUDGET ESTIMATES OF THE FINANCIAL YEAR 2023-24 FOR UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR:**

- (a) The total receipts of 2023-24 are estimated at Rs 1,18,500 crore. Of which, Rs.1,06,061 crore are revenue receipts, Rs. 12,439 crore are capital receipts and Rs 30,000 crore are Ways & Means Advances. The own revenues both tax and non-tax are estimated to be Rs. 34,942 crore. In addition to this, Rs 35,581 crore are to flow as central assistance and Rs. 26,786 crore as CSS/ PMDP to Union Territory of Jammu and Kashmir.
- (b) Given these receipts, the total expenditure is estimated to be Rs 1,18,500 crore of this, capital expenditure would be Rs 41,491 crore and revenue expenditure Rs 77,009 crore.



(c) The Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (02) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs 1,48,500 crore from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the period w.e.f 1st April, 2023 to 31<sup>st</sup> March, 2024.

34. **Fiscal Indicators:**

(a) The tax/GDP ratio is projected at 8.82 % for 2023-24 which is higher than the previous year of 7.77 %.

(b) Debt/GDP ratio for 2023-24 is 49 %.

(c) GDP growth for the year 2023-24 has been projected at Rs. 2,30,727 crore which shows a growth of 10 % over the previous year.

35. Mr. Speaker Sir, with these words, I commend the Supplementary Budget (for 01.04.2022 to 31.03.2023), and Budget for the year 2023-24 of the Union Territory of Jammu & Kashmir to this August House for further consideration.

